PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 031
दि. 31.05.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बदलती तस्वीर, बढ़ती चुनौतियां: महिलाओं की सेहत और सशक्तिकरण पर नई रिपोर्ट ने दिखाया भारत का सच

नई दिल्ली। देश में महिलाओं की स्थिति को लेकर लंबे समय से चल रही बहस के बीच नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) 2023-24 की नई रिपोर्ट ने एक ऐसी तस्वीर पेश की है, जिसमें उपलब्धियों की चमक भी दिखाई देती है और चुनौतियों की परछाइयां भी। रिपोर्ट बताती है कि एक ओर महिलाएं पहले की तुलना में अधिक शिक्षित, अधिक डिजिटल रूप से जुड़ी हुई और आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई समस्याएं तेजी से उभर रही हैं। विशेष रूप से महिलाओं में बढ़ता मोटापा, शिशु पोषण में गिरावट और परिवार नियोजन के आधुनिक साधनों के उपयोग में कमी ऐसे संकेत हैं, जो भविष्य के लिए चिंता पैदा करते हैं।

देश के स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक विकास की दिशा को समझने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण को सबसे महत्वपूर्ण अध्ययनों में गिना जाता है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से सरकारों, नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को यह समझने में मदद मिलती है कि देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और किन क्षेत्रों में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट भी कई ऐसे तथ्य सामने लेकर आई है, जो भारत में महिलाओं और बच्चों की बदलती स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले सर्वेक्षण की तुलना में मोटापे की दर में लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती जीवनशैली, शारीरिक गतिविधियों में कमी, फास्ट फूड और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का बढ़ता सेवन तथा लंबे समय तक बैठे रहने की आदत इस स्थिति के प्रमुख कारण हैं। मोटापा केवल शरीर के वजन का मामला नहीं है, बल्कि यह मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हार्मोनल असंतुलन और कई अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। यही वजह है कि स्वास्थ्य

विशेषज्ञ इसे आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक मान रहे हैं।

दिलचस्प बात यह है कि महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के संकेत भी इसी रिपोर्ट में दिखाई देते हैं। कामकाजी महिलाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले सर्वेक्षण में जहां केवल 25.4 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रोजगार या आय अर्जित करने वाली गतिविधि से जुड़ी थीं, वहीं अब यह आंकड़ा बढ़कर 30.8 प्रतिशत हो गया है। यह परिवर्तन केवल रोजगार के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं की आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक भागीदारी में भी बढ़ोतरी का संकेत देता है।

डिजिटल दुनिया में भी महिलाओं की उपस्थिति तेजी से बढ़ी है। रिपोर्ट के अनुसार अब 64.3 प्रतिशत महिलाएं इंटरनेट का उपयोग कर रही हैं। यह संख्या पिछले वर्षों की तुलना में लगभग दोगुनी है। इंटरनेट तक पहुंच बढ़ने से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और रोजगार के नए अवसरों से जुड़ने में मदद मिली है। विशेषज्ञ इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं।

हालांकि सामाजिक विकास के मोर्चे पर कुछ उत्साहजनक खबरें भी सामने आई हैं। घरेलू हिंसा के मामलों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार पहले जहां 29.2 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होने की बात कहती थीं, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर 22.3 प्रतिशत रह गया है। यह बदलाव समाज में बढ़ती जागरूकता, कानूनी संरक्षण, महिला सहायता सेवाओं और शिक्षा के बढ़ते स्तर का परिणाम माना जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकड़ा अभी भी चिंताजनक है, क्योंकि हर पांच में से लगभग एक महिला अब भी किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा का सामना कर रही है।

बाल विवाह के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। देश में बाल विवाह की दर 23.3 प्रतिशत से घटकर 20.1 प्रतिशत हो गई है। यह परिवर्तन दर्शाता है कि शिक्षा, सरकारी योजनाओं और सामाजिक जागरूकता अभियानों का प्रभाव धीरे-धीरे दिखाई देने लगा है। हालांकि कई राज्यों में यह समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए लगातार प्रयासों की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला तथ्य निजी अस्पतालों में बढ़ती सिजेरियन डिलीवरी की दर है। निजी अस्पतालों में अब 54.1 प्रतिशत प्रसव सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से हो रहे हैं। यह आंकड़ा चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जहां जरूरत हो वहां सिजेरियन प्रसव जीवनरक्षक साबित होता है, लेकिन अनावश्यक सिजेरियन की बढ़ती प्रवृत्ति स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए चिंता का विषय हो सकती है।

नवजात शिशुओं के पोषण से जुड़े आंकड़े भी मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं। जन्म के बाद पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान कराने की दर में गिरावट दर्ज की गई है। पहले जहां 63.7 प्रतिशत माताएं अपने बच्चों को शुरुआती छह महीनों तक केवल स्तनपान कराती थीं, वहीं अब यह संख्या घटकर 55.8 प्रतिशत रह गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार शिशु के जीवन के पहले छह महीने उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान केवल स्तनपान को सबसे सुरक्षित और पौष्टिक आहार माना जाता है। ऐसे में इस दर में गिरावट चिंता का विषय मानी जा रही है।

हालांकि बच्चों में कुपोषण के कुछ संकेतों में सुधार देखने को मिला है। नाटेपन या स्टंटिंग से प्रभावित बच्चों का प्रतिशत 35.5 से घटकर 29.3 हो गया है। यह दर्शाता है कि पोषण योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि छह महीने से दो वर्ष तक के केवल 15.3 प्रतिशत बच्चों को ही संतुलित और पर्याप्त आहार मिल पा रहा है। यह आंकड़ा बताता है कि पोषण के क्षेत्र में अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है।

बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के मामले में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार अब 98.3 प्रतिशत घरों तक बिजली पहुंच चुकी है और 96.5 प्रतिशत परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। यह बदलाव ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बेहतर बिजली और स्वच्छ जल की उपलब्धता सीधे तौर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है।

महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में भी सुधार दर्ज किया गया है। अब 18.8 प्रतिशत परिवारों में महिलाओं के नाम पर जमीन या मकान का स्वामित्व दर्ज है। हालांकि यह संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम है, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में यह एक सकारात्मक संकेत है। संपत्ति पर महिलाओं का

परीक्षा व्यवस्थाओं पर राहुल गांधी का हमला, बोले एक करोड़ छात्रों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़

नई दिल्ली। देश में विभिन्न प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) में आई तकनीकी समस्याओं को मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से आयोजित कराने में लगातार विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर देश को 'विश्वगुरु' बनाने की बात करती है, जबकि दूसरी ओर करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा तंत्र को भी सही ढंग से संचालित नहीं कर पा रही है।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने संदेश में हाल के महीनों में आयोजित प्रमुख परीक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट), सीबीएसई की परीक्षाएं, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की परीक्षा और अब सीयूईटी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में लगातार

समस्याएं सामने आई हैं। उन्होंने लिखा कि इन चार परीक्षाओं में लगभग एक करोड़ छात्र शामिल हुए, लेकिन इनमें से एक भी परीक्षा पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ आयोजित नहीं की जा सकी। उनके अनुसार यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि देश के युवाओं के सपनों और भविष्य से जुड़ा गंभीर मामला है।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही खामियां लाखों विद्यार्थियों के लिए चिंता, असुरक्षा और मानसिक दबाव का कारण बन रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं, अपने करियर और भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जब परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियां, तकनीकी समस्याएं, प्रश्नपत्र विवाद या आयोजन संबंधी कमियां सामने आती हैं तो सबसे बड़ा नुकसान छात्रों को उठाना पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं के धैर्य और विश्वास की भी एक सीमा होती है और जिस पीढ़ी के भविष्य के साथ बार-बार खिलवाड़ किया जा रहा है, वही आने वाले समय में जवाब भी मांगेगी। अपने बयान में राहुल गांधी ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री Narendra Modi पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकताएं छात्रों और युवाओं की समस्याओं के समाधान की बजाय अपनी छवि को बनाए रखने पर अधिक केंद्रित दिखाई देती हैं। कांग्रेस नेता का आरोप है कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगातार सामने आ रही समस्याओं के बावजूद जवाबदेही तय नहीं की जा रही और न ही जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी राहुल गांधी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने सीबीएसई से जुड़े एक मामले को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उस समय उन्होंने आरोप लगाया था कि शिक्षा क्षेत्र में लगातार सामने आ रही कथित विफलताओं के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि इससे यह संदेश जाता है कि सरकार को छात्रों के भविष्य से अधिक अपनी राजनीतिक छवि की चिंता है। कांग्रेस का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही समस्याओं ने विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के बीच अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। पार्टी का दावा है कि परीक्षा आयोजन से जुड़ी संस्थाओं की कार्यप्रणाली की समीक्षा किए जाने और जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

सीमा सुरक्षा पर अमित शाह का सख्त संदेश, घुसपैठ और अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी

भुज। देश की आंतरिक और सीमाई सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत-पाकिस्तान सीमा से लगे सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने सीमा प्रबंधन को और अधिक प्रभावी, आधुनिक तथा समन्वित बनाने पर जोर देते हुए अधिकारियों को घुसपैठ, तस्करी और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

भुज में आयोजित इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी तथा सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े विभिन्न मुद्दों, तटीय सुरक्षा, घुसपैठ की रोकथाम, अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण तथा सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। गृह मंत्री ने कहा कि गुजरात की सीमाएं केवल राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अमित शाह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में गुजरात के सुरक्षा परिदृश्य में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने इसका श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय, आधुनिक तकनीक के उपयोग, मजबूत सीमा बाड़बंदी, तटीय सुरक्षा तंत्र के विस्तार तथा सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता को दिया। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के कारण राज्य में घुसपैठ और सीमा पार से होने वाली तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निरंतर निगरानी और समयबद्ध कार्रवाई ने सीमाई क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को मजबूत किया है।

बैठक में गृह मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे शून्य से 15 किलोमीटर क्षेत्र को विशेष संवेदनशील क्षेत्र बताते हुए यहां किसी भी प्रकार के अनधिकृत अतिक्रमण के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा केवल सैनिकों और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि स्थानीय प्रशासन और नागरिक तंत्र की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस पूरे क्षेत्र में मौजूद हर प्रकार के अवैध निर्माण, अतिक्रमण या संदिग्ध गतिविधि की पहचान कर उसे समाप्त किया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

अमित शाह ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की भूमिका को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय बदलावों पर लगातार निगरानी रखी जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आबादी से जुड़े असामान्य परिवर्तनों, संदिग्ध गतिविधियों और बाहरी तत्वों की मौजूदगी पर नियमित रिपोर्ट तैयार कर राज्य और केंद्र सरकार को भेजी जाए। उनका कहना था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव भी भविष्य में बड़े सुरक्षा जोखिम का कारण बन सकते हैं, इसलिए प्रशासन को पूरी सतर्कता के साथ काम करना होगा।

गृह मंत्री ने अवैध रूप से बसे घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि यह कार्य केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रशासनिक और राजस्व तंत्र के हर स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने पुलिस थानों से लेकर तहसील और पटवारी स्तर तक सभी अधिकारियों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया ताकि अवैध घुसपैठियों की पहचान, सत्यापन और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया प्रभावी ढंग से पूरी की जा सके।

बैठक के दौरान तटीय सुरक्षा व्यवस्था की भी विस्तृत समीक्षा की गई। गुजरात की लंबी समुद्री सीमा को देखते हुए गृह मंत्री ने समुद्री निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री मार्गों का उपयोग कर घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आधुनिक तकनीक और खुफिया तंत्र का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और नियमित निगरानी से सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सजेगा महामुकाबला, गुजरात और बेंगलुरु में कौन बनेगा आईपीएल का नया बादशाह?

अहमदाबाद। लगभग दो महीनों तक चले रोमांच, संघर्ष, रिकॉर्ड, उलटफेर और यादगार प्रदर्शनों के बाद इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 अपने सबसे महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गया है। रविवार को अहमदाबाद के भव्य नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाला फाइनल मुकाबला तय करेगा कि इस सीजन की चमचमाती ट्रॉफी पर आखिर किस टीम का कब्जा होगा। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मैदान पर केवल दो टीमें नहीं, बल्कि दो अलग-अलग क्रिकेट दर्शन, दो कप्तानों की रणनीति और कई स्टार खिलाड़ियों का गौरव दांव पर लगा होगा।

आईपीएल का यह सीजन शुरू से ही रोमांच से भरपूर रहा। कई बार ऐसा लगा कि कोई टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है, लेकिन उसने शानदार वापसी कर सबको चौंका दिया। वहीं कुछ मजबूत मानी जाने वाली टीमें उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं। लेकिन अंततः गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निरंतरता, संतुलन और दबाव के क्षणों में बेहतर प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। अब दोनों टीमों के सामने केवल एक आखिरी चुनौती है, जिसे पार कर वे इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर सकती हैं।

गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए यह मुकाबला विशेष महत्व रखता है। टीम लगातार दूसरे वर्ष फाइनल में पहुंची है और लगातार दूसरा खिताब जीतने का सुनहरा अवसर उसके सामने है। पूरे सीजन में बेंगलुरु ने एक संतुलित इकाई के रूप में खेल दिखाया है। बल्लेबाजी में जहां अनुभव और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला, वहीं गेंदबाजों ने भी निर्णायक मौकों

पर टीम को सफलता दिलाई। कप्तान रजत पाटीदार ने शांत और परिपक्व नेतृत्व का परिचय देते हुए टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालकर फाइनल तक पहुंचाया है। उनकी कप्तानी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने हर खिलाड़ी की क्षमता का सही समय पर उपयोग किया।

दूसरी ओर गुजरात टाइटंस अपने घरेलू मैदान पर खेलने का लाभ उठाने की कोशिश करेगी। पांच वर्षों में तीसरी बार फाइनल में पहुंची यह टीम आईपीएल की सबसे सफल और स्थिर फ्रेंचाइजियों में गिनी जाने लगी है। गुजरात ने इस सीजन में अपने हर विभाग में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। बल्लेबाजों ने लगातार रन बनाए हैं, गेंदबाजों ने विपक्षी टीमों को दबाव में रखा है और फील्डिंग के स्तर पर भी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। घरेलू दर्शकों का समर्थन निश्चित रूप से गुजरात के आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा।

इस फाइनल की सबसे दिलचस्प कहानी दोनों युवा कप्तानों के इर्द-गिर्द घूमती है। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी नेतृत्व क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया है। शुभमन गिल जहां अपनी शानदार बल्लेबाजी और आक्रामक सोच के लिए जाने जाते हैं, वहीं रजत पाटीदार ने शांत स्वभाव और रणनीतिक फैसलों से टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। फाइनल में केवल खिलाड़ियों की नहीं, बल्कि इन दोनों कप्तानों की रणनीति की भी कड़ी परीक्षा होगी।

क्रिकेट प्रेमियों की नजरें एक बार फिर विराट कोहली पर भी टिकी रहेंगी। आईपीएल इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल विराट ने इस सीजन में भी अपनी क्लास और अनुभव का परिचय दिया है। 9000 से अधिक आईपीएल रन बनाने वाले पहले और एकमात्र बल्लेबाज के रूप में उन्होंने पहले ही कई रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं। फाइनल जैसे बड़े मुकाबलों में विराट का अनुभव बेंगलुरु के लिए अमूल्य साबित हो सकता है। प्रशंसकों को उम्मीद होगी कि क्रिकेट का यह महान सितारा एक बार फिर बड़े मंच पर यादगार पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाए।

गुजरात की ओर से भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल की बल्लेबाजी, मध्यक्रम की स्थिरता और गेंदबाजी आक्रमण की धार टीम की सबसे बड़ी ताकत रही है। पूरे सीजन में गुजरात ने सामूहिक प्रदर्शन के दम पर सफलता हासिल की है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति मानी जा रही है। टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रही, बल्कि अलग-अलग मुकाबलों में अलग-अलग खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली है।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम एक बार फिर ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हजारों दर्शकों की मौजूदगी और करोड़ों लोगों की नजरें इस फाइनल को और भी खास बना देंगी। इस मैदान ने पहले भी कई बड़े मुकाबले देखे हैं, लेकिन आईपीएल फाइनल का रोमांच हमेशा अलग होता है। यहां का माहौल, दर्शकों का उत्साह और ट्रॉफी जीतने का दबाव खिलाड़ियों की असली परीक्षा लेता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि फाइनल में वही टीम सफल होगी जो दबाव को बेहतर तरीके से संभालेगी। बड़े मुकाबलों में अक्सर आंकड़े और पिछले रिकॉर्ड ज्यादा मायने नहीं रखते। यहां मानसिक मजबूती, सही रणनीति और निर्णायक क्षणों में बेहतर प्रदर्शन ही जीत और हार का अंतर तय करते हैं। दोनों टीमों के पास मैच विजेता खिलाड़ी हैं और दोनों ही इस मंच तक पहुंचने की पूरी हकदार हैं।

इस सीजन में आईपीएल ने एक बार फिर साबित किया है कि यह केवल क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भावनाओं, सपनों और जुनून का उत्सव है। युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला, अनुभवी खिलाड़ियों ने अपनी उपयोगिता साबित की और प्रशंसकों को लगातार रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। अब इस लंबे सफर का अंतिम अध्याय लिखा जाना बाकी है।

रविवार की रात जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रोशनी के बीच विजेता टीम ट्रॉफी उठाएगी, तब एक टीम के लिए यह जश्न और इतिहास रचने का क्षण होगा, जबकि दूसरी टीम के लिए अधूरा सपना। लेकिन उससे पहले क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐसे मुकाबले का इंतजार है जिसमें हर गेंद, हर रन और हर विकेट खिताब की दिशा तय कर सकता है। अहमदाबाद तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं और करोड़ों प्रशंसक भी तैयार हैं। अब देखना यह है कि आईपीएल 2026 की बादशाहत गुजरात टाइटंस के हाथों में जाती है या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार चैंपियन बनकर नया इतिहास रचती है।

संपादकीय

जन के हित के हेत

भले ही हिंदी पत्रकारिता गफलत में अपनी पहली शताब्दी न मना सकी हो, लेकिन वह द्विशताब्दी के मौके पर खासी उत्साहित है। वह आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है। आज से दो सौ साल पहले उत्तर भारत से जाकर तत्कालीन कलकत्ता को कर्मभूमि बनाने वाले पं. युगल किशोर शुक्ल ने 'उदन्त मार्तण्ड' के रूप में हिंदी पत्रकारिता का बीजारोपण किया था। भले ही वह पत्र आर्थिक झंझावातों से अधिक समय तक न चल सका, लेकिन अपनी 'आदि प्रतिज्ञा' से वह जो पत्रकारिता का लक्ष्य तय कर गया, वह आज भी उतना ही जरूरी व प्रासंगिक है। 'उदन्त मार्तण्ड' के प्रवेशांक में पं. शुक्ल ने लिखा था कि इस समाचार पत्र का प्रकाशन- ' हिंदुस्तानियों के हित के हेत' .. किया जा रहा है। निस्संदेह, ध्येय वाक्य के गहरे निहितार्थ थे और आज भी हैं। सही मायने में पत्र ने दो सदी पहले पत्रकारों को उनका 'कर्मपथ' बता दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जबकि यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र था, लेकिन उसकी फिक्र केवल हिंदी भाषियों की ही नहीं थी। उसकी 'आदि प्रतिज्ञा' समस्त हिंदुस्तानी समाज के हित को लेकर थी। पत्र का नाम 'उदन्त मार्तण्ड' यानी उगता सूरज था। बाकायदा समाचार पत्र के नाम के साथ संस्कृत में लिखा होता था कि जैसे सूरज के प्रकाश के बिना अंधेरा दूर नहीं होता, उसी तरह अज्ञ जन समाचार पत्र के बिना ज्ञानवान नहीं बन सकते। यह भी कि ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के मकसद से इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है। निश्चय ही उदन्त मार्तंड की 'आदि प्रतिज्ञा और धेय' में सभी भाषाओं की पत्रकारिता का लक्ष्य आज भी यही है। निश्चय ही यह पत्रकारिता बिरादरी को आईना दिखाता है कि हमारी पत्रकारिता हर हिंदुस्तानी के हित के हेत है? क्या हम हम समाज में अज्ञ को ज्ञानवान बनाने का काम कर रहे हैं? क्या हमारे शब्द उतने ही अर्थवान व सारवान हैं, जितना इस पेशे से अपेक्षित है। निश्चय ही यह अवसर पत्रकारिता बिरादरी को आत्ममंथन का मौका देता है।

हिंदी पत्रकारिता के प्रतीक पुरुष स्व. प्रभाष जोशी ने एक बार पत्रकारिता के छात्रों से बातचीत करते हुए कहा था कि पत्रकारिता 'ऋषिकर्म' है। जिसमें घर फूंक तमाशा देखने का जज्बा हो, वही पत्रकारिता में आए। पैसे कमाने के लिये तमाम पेशे हैं। साथ ही यह भी कि किसी डेढ़ पेज की प्रेस विज्ञप्ति में यदि कोई डेढ़ लाइन की खबर निकाल सके, तो वही असली पत्रकार है। बाकी सब विज्ञापन है। लेकिन विडंबना यह है कि आज विश्वविद्यालयों से निकलने वाले पत्रकारिता के छात्रों में बिरले ही ऐसे होते हैं, जो वेतन, पैकेज व पद के सम्मोहन से मुक्त होकर मिशनरी पत्रकारिता का जज्बा रखते हों। आज पत्रकारिता के नवसाक्षरों की बड़ी फौज पत्रकारिता के ग्लैमर व प्रसिद्धि के प्रलोभन में इस पेशे में आती है। उसे आजादी की लड़ाई में सर्वस्व अर्पित करने वाले 'स्वराज' अखबार का शायद ही भान हो, जिसके ढाई वर्ष के अल्पकाल में संपादकों को डेढ़ सौ साल की सजाएं हुई। लेकिन उसके बावजूद संपादक पद के लिये विज्ञापन देने पर जज्बे के पत्रकारों की लाइन लग जाती थी। निश्चित रूप से पत्रकारिता जीवन मूल्यों की शुचिता व सामाजिक दायित्वों का पेशा है। यह विशुद्ध कारोबार या व्यवसाय नहीं हो सकता है। विडंबना यह है कि तकनीकी क्रांति के बाद जब से बड़ी पूंजी की समाचारों के प्रकाशन में दखल बढ़ी है, तब से संपादक नामक संस्था क्षीण हुई है और पूंजीपति की दखल में वृद्धि हुई है। पिछली सदी में एक दिग्गज संपादक की वह टिप्पणी आज भी प्रासंगिक है कि 'भविष्य के अखबार रूप-रंग व प्रकाशन में तो आकर्षक होंगे, लेकिन उनमें पत्रकारिता की आत्मा न होगी।' निश्चय ही आज बाजार और राजनीति की दखल के चलते पत्रकारिता के समक्ष बड़ी चुनौती बनी है। वहीं नई पीढ़ी के कथित ऑनलाइन व डिजिटल सम्मोहन के चलते प्रिंट पत्रकारिता से छिटकना भी चिंता की बात है। कॉन्वेंट स्कूलों से निकलने वाले छात्र हिंदी भाषायी समाचार पत्रों से विमुख हुए हैं। उनका समाचार पत्रों से विमुख होना भारतीय परिवेश, संस्कृति व मातृभाषा से दूर होना भी है। ये संपादकों को सोचना होगा कि समाचार पत्रों से नई पीढ़ी का लगाव कैसे गहरा किया जाए।

रीलसमय सब जग जानी

> " पत्रकारिता के जब भी नए माध्यम सामने आए, पुराने माध्यम के खात्मे की आशंका जताई जाती रही। हालांकि नए माध्यम के किंचित गुणों के साथ प्रतियोगिता और साम्यता बरतते हुए पुराने माध्यम ने जहां खुद को ज्यादा प्रतियोगी बनाया। हर नए माध्यम के अवतार और विकास के मूल में नई तकनीक रही है।

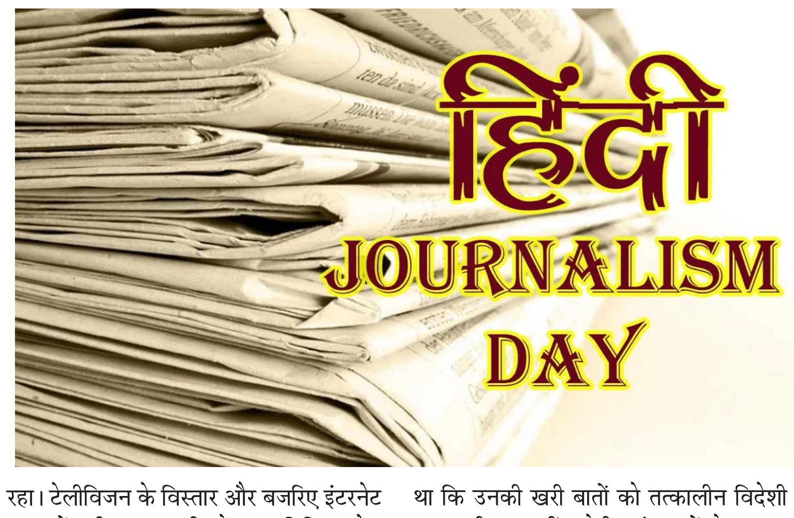

तुलसी के लिए समूचा विश्व ही श्रीराम और सीता की तरह रहा। आज की पत्रकारिता पर जिधर भी नजर फिराएं, कुछ उसी तरह टीवी मय ही लगती है। लगता नहीं कि मीडिया की की दुनिया में अखबार भी हैं, पत्रिकाएं भी हैं, रेडियो भी है और सबसे अहम इंटरनेट भी है। दो सौ साल की हिंदी पत्रकारिता का इतिहास गरिमा के सोपानों से भरा हुआ है। नवजागरण को बढ़ावा देने, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन मूल्यों की स्थापना में हिंदी पत्रकारिता ने महती भूमिका निभाई है। स्वाधीनता आंदोलन की कोख से उपजी हिंदी पत्रकारिता ने स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ी, हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान का माध्यम भी बनी, लेकिन दो सौ साल की यात्रा के उपरांत बाद के वर्षों के उसके इतिहास को देखते हैं तो वह सिर्फ टीवीमय नजर आती है, टीवी से भी आगे बढ़कर वह रीलमय नजर आती है। छापे से शुरू हिंदी पत्रकारिता का यह रूप छापे और रेडियो की उपस्थिति के बावजूद आज वह रील्स के इर्द-गिर्द घूमती नजर आ रही है। टेलीविजन तक तो स्थिति ठीक थी, लेकिन उसके बाद की जब तकनीक के सहारे टीवी की दुनिया में चुपके से रील्स ने दखल देनी शुरू की तो स्थितियां बदलने लगीं। हर नई तकनीक की अपनी कुछ खासियत होती है और इसके साथ ही वह अपना चरित्र भी विकसित करती है। रील्स का जो चरित्र विकसित हुआ है, उसमें उथलापन ज्यादा है, गंभीरता कम है।इसे समझने के लिए छापा यानी प्रेस से मीडिया तक की यात्रा को गंभीरता से देखना और समझना होगा। रेडियो के आविष्कार और फिर टेलीविजन के विस्तार के पहले तक पत्रकारिता की बुनियाद में छापेखाने ही रहे। शुरूआती दौर में पत्रकारिता को प्रेस इसी वजह से कहा गया। जब तक उसकी पहचान के साथ प्रेस जुड़ा रहा, उसके प्रति विशिष्टताबोध बना रहा। टेलीविजन के विस्तार और बजरिए इंटरनेट माध्यमों की आवाजाही ने इस विशिष्टाबोध युक्त पहचान को मीडिया में रूपांतरित कर दिया है। इस यात्रा में मोटे तौर पर पत्रकारिता के दो रूप दिखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन की कोख से जन्मे छापे की पत्रकारिता कोख में मिले संस्कारों को अब तक कमोबेश अपनाए रखा है। बाद में आए रेडियो और टीवी में तकनीक भले ही प्रधान रहा,लेकिन उनके मूल में भी छापे की ही पत्रकारिता रही। इसके बावजूद तकनीक प्रधान और अत्याधुनिक माध्यम टीवी छापे की बुनियादी मूल्यों से काफी दूर दिखता है।

उदंत मार्तंड के प्रकाशक और संपादक जुगल किशोर शुक्ल हों या बंगाल गजट निकालने वाले जेम्स ऑगस्टस हिक्की, उन्हें अखबार निकालने का गहरा युगबोध था। लेकिन उन्हें पता था कि वह जो कार्य करने जा रहे हैं, वह बेहद दुष्कर है। उनके सामने संसाधनों की ही चुनौतियां ही नहीं थी, पाठक जुटाना और अपने छापे की बात उन तक पहुंचाना भी आसान नहीं था। उन्हें आभास था कि उनकी खरी बातों को तत्कालीन विदेशी सत्ता स्वीकार नहीं करेगी। संसाधनों के अभाव और सरकारी सहयोग नहीं मिलने की वजह से ही उदंत मार्तंड असमय कालकवलित हो गया। उसे संसाधन या सरकारी सहयोग इसलिए नहीं मिले, क्योंकि उसका स्वर भारतोन्मुखी था, वह हिंदी समाज के हित के हेत निकल रहा था, उसे भारतीय मूल्यों की चिंता थी और भारतीय समाज के नवजागरण में वह भागीदार बनना चाहता था। यह कहानी उदंत मार्तंड तक ही सीमित नहीं रही। बाद के दिनों में भी हिंदी में तमाम समाचार पत्र निकले और बंद होते रहे। इस लिहाज से कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का इतिहास नवजागरण का ही इतिहास नहीं है, अखबारों के निकलने और बंद बंद होने के सिलसिले का भी इतिहास है। लेकिन इस सिलसिले में भी समानता दिखती है, पत्रों का मूल उद्देश्य भारतीय मूल्यों, स्वाधीन सोच के लिए जागरण पैदा करना और राष्ट्र हित पर खुद को तिरोहित करना ज्यादातर पत्रों के प्रकाशन के मूल में दिखता है। कह सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता के जीन यानी गुणसूत्र में तिरोहित होने का ही भाव रहा है। यही वजह है कि हिंदी पत्र खतरा उठाते हुए भारतीयता की बात करना और सार्वजनिक हित का सवाल उठाना अपना पुनीत कर्तव्य मानते रहे। बेशक आज के समाचार पत्र भी सवालों के घेरे में हैं, लेकिन सवालों में आना सिर्फ अखबारी संस्थानों और उनके कर्ताधर्ताओं की सोच का ही मसला नहीं है, बल्कि उदारीकरण के बाद बढ़ी अर्थप्रधानता और पूंजी के खेल से उपजी मजबूरी भी है। फिर भी जब तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के साथ जिन मूल्यों को भारतीय समाज ने स्वीकार किया और आत्मसात किया है, उन्हें अब भी अखबारों ने ही आत्मसात कर रखा है। इनकी तुलना में टीवी की पत्रकारिता कहीं ज्यादा चंचल और चलायमान नजर आती है।

पत्रकारिता के जब भी नए माध्यम सामने आए, पुराने माध्यम के खात्मे की आशंका जताई जाती रही। हालांकि नए माध्यम के किंचित गुणों के साथ प्रतियोगिता और साम्यता बरतते हुए पुराने माध्यम ने जहां खुद को ज्यादा प्रतियोगी बनाया। हर नए माध्यम के अवतार और विकास के मूल में नई तकनीक रही है। तकनीक की एक विशेषता है, हर नई तकनीक हमेशा पुरानी के मुकाबले ज्यादा प्रभावी होती है। इस लिहाज से छापे के बाद आए रेडियो ने लोगों को ज्यादा लुभाया। लेकिन रेडियो के साथ प्रतियोगिता में छापे ने हार नहीं मानी और उसके बरक्स खुद को भी पहले तुलना में ज्यादा गतिमान बनाया, अपने कंटेंट और प्रस्तुति में विविधता और नवीनता की खोज की। इसके बाद अखबारों का प्रसार बढ़ा, रेडियो को तो वैसे ही अपनी नई तकनीक के चलते आगे बढ़ना ही था। जब टेलीविजन ने मीडिया की दुनिया में अगले चरण के रूप में कदम रखा, दोनों पुराने माध्यमों के खात्मे की आशंका जताई जाने लगी। हालांकि कोई खत्म नहीं हुआ, रेडियो ने खुद के लिए नई तकनीक यानी फ्रीक्वैंसी मॉड्युला यानी एफएम की ईजाद कर ली और अपने लिए जीवन की नई राह खोज ली तो अखबारों ने अपने पन्ने टेलीविजन के पर्दे की तरह चमकादार और दृश्यवान बनाने लगे। अखबारों पर विजुअल का प्रभाव फोटो और चित्रों के विस्तार के रूप में दिखा। इसके असर से अखबार अब भी बचे हुए हैं, रेडियो भी जिंदा है और टेलीविजन भी विस्तृत हो चुका है। लेकिन जिसे हम टेलीविजन कहते हैं, जिसमें एक पर्दा होता है, उसे चुनौती रील्स और ऐसे ही शॉर्ट वीडियो माध्यमों से मिल रही है। टेलीविजन को पहले इंटरनेट से चुनौती मिली, लेकिन बाद के दिनों इंटरनेट ने खुद में मीडिया के हर फॉर्मेट को समाहित कर लिया। इसी बीच रील्स और टिकटैक जैसे शॉर्ट फॉर्मेट आ गए और टेलीविजन को भी चुनौती मिलने लगी।

मीडिया के शुरूआती दोनों माध्यम जहां मूल्यों और संघर्ष की कशमकश वाले दौर में पैदा हुए, पले और बढ़े, इसलिए उनके चरित्र पर मूल्यों और संघर्ष का असर दिखता है। लेकिन टेलीविजन का वैश्विक प्रसार आर्थिक उदारीकरण के दौर में हुआ है। इसलिए उसने उदारीकरण की विशेषताओं को भी आत्मसात कर लिया है। उदारीकरण की पहली शर्त चमक-दमक और शोशेबाजी है। भारतीय परिदृश्य में जब टेलीविजन माध्यम विकसित हो रहा था, तब हिंदी के गंभीर पत्रकारों ने इससे दूरी बनाए रखी। उन्होंने तब इसे दोयम दर्जे का माध्यम माना और उसकी उपेक्षा की। उन्हें ऐसा लगा कि यह गंभीर पत्रकारिता का माध्यम नहीं हो सकता।

प्रेरणा

छोटे कर्मों की शक्ति: सफलता की महान सीढ़ी

इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी सफलता किसी एक बड़े अवसर या अचानक मिले सौभाग्य का परिणाम नहीं थी। उनके जीवन की ऊंचाइयों के पीछे अनगिनत छोटे-छोटे कार्य, साधारण दिखाई देने वाले प्रयास और हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने की आदत छिपी होती है। अक्सर लोग जीवन में किसी बड़े अवसर, बड़ी जिम्मेदारी या बड़े मंच का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि जब उन्हें कोई महत्वपूर्ण काम मिलेगा, तभी वे अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। महानता की शुरुआत हमेशा छोटे कार्यों से होती है। जो व्यक्ति साधारण जिम्मेदारियों को असाधारण समर्पण के साथ निभाता है, वही भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियों का अधिकारी बनता है।

16वीं शताब्दी के जापान की एक घटना इस सत्य को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। एक युवा सेवक था, जिसका नाम हिदेयोशी था। उसका जीवन किसी सामान्य सेवक की तरह था। वह अपने स्वामी के जूते व्यवस्थित करता, अस्तबल की सफाई करता और सैनिकों की छोटी-छोटी आवश्यकताओं का ध्यान रखता था। उसके पास कोई बड़ा पद नहीं था, न ही कोई विशेष अधिकार। वह उन लोगों में से था जिन्हें सामान्यतः कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी विशेषता थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी—वह हर छोटे कार्य को भी पूरे मन और समझदारी के साथ करता था।

एक सर्द सुबह उसके स्वामी को युद्ध परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में जाना था। जब उन्होंने अपने जूते पहने तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि जूते भीतर से गर्म थे। उन्होंने कारण पूछा तो हिदेयोशी ने विनम्रता से बताया कि रात बहुत ठंडी थी और उसे लगा कि ठंडे जूते पहनने से स्वामी को असुविधा होगी। इसलिए उसने उन्हें अपने वस्त्रों के भीतर रखकर गर्म कर लिया था। वहां उपस्थित कई लोग इस बात पर हंस पड़े। उन्हें यह एक मामूली और हास्यास्पद बात लगी। लेकिन उसके स्वामी ने उस घटना में कुछ और देखा। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पहचाना जो केवल आदेशों का पालन नहीं करता था, बल्कि दूसरों की आवश्यकता को पहले से समझने की क्षमता रखता था। यही क्षमता किसी भी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाती है। अधिकांश लोग केवल उतना ही करते हैं जितना उनसे कहा जाता है। वे अपने कर्तव्य को एक बोझ की तरह निभाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य के पीछे छिपी आवश्यकता को समझते हैं। वे सोचते हैं कि किसी काम को और बेहतर कैसे किया जा सकता है। यही सोच उन्हें भीड़ से अलग करती है। हिदेयोशी का जीवन आगे बढ़ता गया। उसे धीरे-धीरे अधिक महत्वपूर्ण कार्य मिलने लगे। उसने हर जिम्मेदारी को उसी लगन और सूझबूझ के साथ निभाया। युद्धों के दौरान वह केवल सेनापतियों के आदेशों तक सीमित नहीं रहा। उसने सैनिकों की थकान, उनके भोजन, उनके आराम और उनके मार्गों तक का ध्यान रखा। उसने यह समझ लिया था कि किसी सेना की शक्ति केवल उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसके सैनिकों की स्थिति में भी होती है। उसकी यही दूरदर्शिता और कार्य के प्रति गंभीरता उसे लगातार आगे बढ़ाती गई। समय के साथ वही साधारण सेवक जापान के सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक बना। यह परिवर्तन किसी चमत्कार का परिणाम नहीं था। यह उन हजारों छोटे कार्यों का परिणाम था जिन्हें उसने कभी छोटा नहीं समझा। जब लोग अवसरों की तलाश में थे, तब वह अपने सामने मौजूद जिम्मेदारियों को श्रेष्ठता के साथ निभाने में लगा था।

यह कहानी केवल इतिहास का एक प्रसंग नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा सिद्धांत भी है। आज के समय में भी लोग अक्सर सफलता को केवल बड़े पद, बड़ी उपलब्धियों या प्रसिद्धि से जोड़कर देखते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि की नींव छोटे प्रयासों से ही तैयार होती है। एक छात्र की सफलता उसकी परीक्षा के दिन नहीं तय होती, बल्कि उन दिनों में तय होती है जब वह नियमित रूप से पढ़ाई करता है। एक खिलाड़ी का विजय मंच पर पहुंचना उसके वर्षों के अभ्यास का परिणाम होता है। एक व्यवसायी की सफलता उसके द्वारा लिए गए छोटे-छोटे सही निर्णयों का फल होती है। छोटे कार्य व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। जब कोई व्यक्ति साधारण परिस्थितियों में भी ईमानदारी, अनुशासन और समर्पण दिखाता है, तब वही गुण उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। बाद में जब बड़ी जिम्मेदारियां उसके सामने आती हैं, तो उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। वह स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है क्योंकि उत्कृष्टता उसकी आदत बन चुकी होती है। जीवन में कई बार लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि उनके पास कोई बड़ा अवसर नहीं है। वे अपने वर्तमान कार्य को महत्वहीन समझने लगते हैं। लेकिन वास्तव में वर्तमान ही भविष्य की तैयारी है। जो व्यक्ति आज अपने छोटे दायित्वों को गंभीरता से नहीं लेता, वह कल बड़ी जिम्मेदारियों को भी सही ढंग से नहीं निभा पाएगा। प्रकृति भी उसी व्यक्ति पर विश्वास करती है जो उपलब्ध अवसरों का सम्मान करता है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी कार्य का महत्व उसके आकार से नहीं, बल्कि उसे करने की भावना से तय होता है। यही कारण है कि एक छोटा सा सद्कार्य भी समाज और जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। किसी की सहायता करना, समय का सम्मान करना, अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करना, दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना—ये सभी छोटे कार्य दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हीं से महान व्यक्तित्वों का निर्माण होता है। हिदेयोशी की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य किसी असाधारण प्रतिभा में नहीं, बल्कि साधारण कार्यों को असाधारण तरीके से करने में छिपा है। जब हम अपने सामने मौजूद छोटी जिम्मेदारियों को महत्व देते हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी और लगन से निभाते हैं, तब हम अनजाने में अपने भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रहे होते हैं। जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले लोग वे नहीं होते जो केवल बड़े अवसरों की प्रतीक्षा करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर छोटे अवसर को सीखने, सेवा करने और स्वयं को बेहतर बनाने का माध्यम बना लेते हैं। यही छोटे कर्म अंततः बड़ी प्रेरणा बनते हैं और साधारण मनुष्य को असाधारण सफलता तक पहुंचा देते हैं।

IB की सीक्रेट रिपोर्ट, 20 दिन में 4 बार बॉर्डर Visit, अमित शाह कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं?

भारत में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका से कितने घुसपैठिए भारत में घुस चुके हैं। सरकार ने हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या में परिवर्तन पे उच्च स्तरीय समिति बनाने का ऐलान कर दिया है और जो नोटिफिकेशन आया है उसमें घुसपैठ यानी इनफिल्ट्रेशन को बार-बार दोहराया गया है। देश की सबसे बड़ी समस्याओं में एक समस्या तमाम राज्यों में चेंज हो रही डेमोग्राफी। वो बात चाहे असम की हो, पश्चिम बंगाल की हो, बात हो बिहार की, उत्तराखंड की, झारखंड की या फिर तमाम और राज्यों की। डेमोग्राफी परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ। ऐसे में बंगाल जीतने के बाद अब एक नई सिरे से प्लानिंग हो रही है। यह प्लानिंग कौन कर रहा है? देश के गृह मंत्री अमित शाह। अगले कुछ दिनों में वो कुछ बहुत बड़े कदम उठाने वाले हैं। एक हफ्ते के अंदर गृह मंत्री अमित शाह बॉर्डर वाले जिलों में तीन चार बार गए हैं। एक बार त्रिपुरा गए। त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, बंगाल। फिर वो बीकानेर, जैसलमेर में थे। यानी वेस्ट बाउंड्री से ले ईस्टर्न बाउंड्री तक लगातार यात्राएं कर रहे हैं। अमित शाह ने खुद को किसी प्रोजेक्ट में इतना इनवॉल्व किया है तो लोगों को सीरियस हो जाना चाहिए। पिछले साल लाल किले से हाई पावर्ड डेमोग्राफिक मिशन की घोषणा की थी और बाद में कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर को 2025 से 11 सितंबर को इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी भी दे दी थी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इस कमेटी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि घुसपैठ और इन अन्य कारणों से अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने कमेटी का गठन कर लिया है। अमित शाह की पोस्ट का पहला शब्द था घुसपैठ। डेमोग्राफिक बदलाव के पूरे नैरेटिव के पीछे घुसपैठ शब्द बड़ा अहम है। पीआईबी ने प्रेस इनफेशन ब्यूरो ने कमेट को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है। पीआईबी के नोटिफिकेशन में लिखा है कि डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक संरचना से जुड़ी गंभीर समस्या है। यह कमेटी अवैध प्रवास यानी घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे डेमोग्राफिक चेंजेस का व्यापक एनालिसिस करेगी और फिर इसका समाधान भी बताएगी। क्या-क्या स्टडी करना है और रिपोर्ट में क्या बताएगी उसको आठ पॉइंट्स में बताया गया है। अलग-अलग इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज और अवैध घुसपैठ से पैदा हुई समस्याओं की स्टडी डेमोग्राफिक चेंज के पीछे के कारण क्या है? क्या बॉर्डर पार की घुसपैठ है? रोजगार के मौके या दूसरे सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े कारण हैं? क्यों कुछ इलाकों में असामान्य तरीके से लोगों की बसावट बढ़ी है? या फिर प्लान करने में यह सब हो गया है। अलग-अलग धर्मों और सामाजिक समुदायों की आबादी में हो रहे बदलावों की स्टडी का फोकस भी उन पॉइंट्स पर है जहां देश की आबादी बढ़ने के सामान्य पैटर्न से अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब अवैध प्रवासियों की पहचान हिरासत और उन्हें डिपोर्ट करने यानी वापस भेजने के लिए आसान निष्पक्ष और तय समय वाली व्यवस्था बनाने के सुझाव भी मांगे गए हैं। और सीमा सुरक्षा जनसंख्या नियंत्रण और आइडेंटिफिकेशन को मजबूत करने के लिए नई व्यवस्था कैसे बने इस पर भी काम होगा। अवैध घुसपैठ और उससे पैदा हुए जनसंख्या असंतुलन से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल के लिए सुझाव की बात भी कही गई है। जरूरत पड़ने पे जनसंख्या बदलाव और घुसपैठ से निपटने के लिए अन्य जरूरी सुझाव भी इसमें निहित है। ये सारे बिंदु पीआईबी के नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं।

गृह मंत्रालय के टेबल पर आईबी की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि जेएनजी आंदोलन के बहाने युवाओं को भड़काने की कोशिश में लगे लोग कौन हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों के पिछले 10-20 पत्थरबाजी की घटनाओं के पैटर्न को देखे तो ज्यादातर घुसपैठिए थे। पत्थरबाजी, आगजनी और सड़कों पर तोड़पोड़ की घटनाओं में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की संलिप्ता वाला भी इंसिडेंट जोड़ा गया है। आईबी की रिपोर्ट बताती है कि चाहे वो दिल्ली दंगे हो या नोएडा में हिंसा हो या कहीं भी अगर पत्थरबाजी होती है तो पत्थर फेंकने वालों की जब पहचान की गई तो इसमें बड़े पैमाने पर रोहिंग्या बांग्लादेशी पकड़े गए। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा गृह मंत्रालय के पास एक और स्पेसिफिक रिपोर्ट है ये कि वेस्टर्न बाउंड्रीज में और ईस्ट में भी खास करके बंगाल में भी जो ड्रग्स का सारा कारोबार चल रहा है वो जो 15 किमी जो बॉर्डर के आसपास का एरिया है वो एक पड़ाव है। जैसे पाकिस्तान से किसी ने फेंका ड्रग्स पंजाब कि बाउंड्री में किसी ने फेंका। उसे कलेक्टर कर 15 किलोमीटर के अंदर और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। गृह मंत्रालय ने एक आर्डर पास किया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी बॉर्डर के 15 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध निर्माण है उसको तुरंत तोड़ा जाए। कुल 50 बीएसएफ के बॉर्डर से बीएसएफ जहां तैनात है वहां से 50 किमी तक पूरी पैनी नजर और हाई सिक्योरिटी होनी चाहिए। आजादी के बाद से देखते हैं घुसपैठ को लेकर क्या-क्या बातें सामने आई। अंग्रेजी न्यूज़ वेबसाइट स्क्रॉल ने अपनी एक रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के हवाले से लिखा है कि 1948 से 1961 के बीच करीब 31 लाख लोग जिनमें ज्यादातर हिंदू थे पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे। पूर्वी पाकिस्तान 1971 में बांग्लादेश हो गया। उस समय असम के मुख्यमंत्री बीपी वाली ने बताया था कि जनवरी 1964 से जनवरी 1965 के बीच करीब 1.8 लाख शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से असम पहुंचे हुए थे। 1997 में तब के गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता ने तब कहा था कि भारत में करीब 1 करोड़ अवैध प्रवासी रह रहे हैं। यह इस तरह का पहला आधिकारिक बयान माना गया था। इंडिया टुडे मैगजीन ने गृह मंत्रालय के एक सूत्र के हवाले से कुछ आंकड़े छापे थे। तब के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 54 लाख, असम में 40 लाख, त्रिपुरा में 8 लाख, बिहार में 5 लाख, महाराष्ट्र में 5 लाख, राजस्थान में 5 लाख और दिल्ली में 3 लाख अवैध प्रवासी बताए गए थे।

अभियान

कलियुग से परे आस्था का द्वीप: नैमिषारण्य की अनंत महिमा और रहस्यमयी आध्यात्मिक विरासत

भारत की पावन भूमि पर ऐसे असंख्य तीर्थ स्थल मौजूद हैं, जिनकी महिमा केवल धार्मिक विश्वासों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हजारों वर्षों की संस्कृति, अध्यात्म, तपस्या और दिव्य परंपराओं के जीवंत साक्षी भी हैं। इन तीर्थों में उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य का स्थान अत्यंत विशिष्ट और अद्वितीय माना जाता है। गोमती नदी के पवित्र तट पर बसा यह प्राचीन तीर्थ सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्रों में गिना जाता है। इसकी पहचान केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे दिव्य क्षेत्र के रूप में की जाती है जहां आज भी कलियुग का प्रभाव प्रवेश नहीं कर पाया है। यही कारण है कि नैमिषारण्य को भारत की आध्यात्मिक राजधानी, ऋषियों की तपोभूमि और देवताओं की प्रिय भूमि कहा जाता है।

सनातन धर्म में समय को चार युगों में विभाजित किया गया है—सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग। प्रत्येक युग की अपनी विशेषताएं और परिस्थितियां बताई गई हैं। जहां सत्ययुग को धर्म, सत्य और तपस्या का युग माना गया, वहीं कलियुग को नैतिक पतन, भौतिकता, स्वार्थ, लालच और अधर्म की वृद्धि का काल बताया गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कलियुग में मनुष्य की आयु कम होगी, उसका धैर्य घटेगा और आध्यात्मिक चेतना कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे समय में यदि कोई स्थान कलियुग के दुष्प्रभावों से मुक्त माना जाता है, तो उसका महत्व स्वतः ही असाधारण हो जाता है। नैमिषारण्य के बारे में यही मान्यता है कि यह वह पावन भूमि है जहां कलियुग की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकतीं। इस मान्यता के पीछे एक अत्यंत रोचक और गहन पौराणिक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद ऋषि-मुनियों को यह चिंता सताने लगी कि द्वापर युग के अंत के साथ कलियुग का आगमन होने वाला है। उन्हें भय था कि कलियुग के प्रभाव से धर्म, सत्य और तपस्या की परंपराएं कमजोर पड़ सकती हैं। तब अनेक महर्षि ब्रह्माजी के पास पहुंचे और उनसे ऐसा स्थान बताने की प्रार्थना की जहां वे कलियुग के प्रभाव से सुरक्षित रहकर साधना कर सकें।

ऋषियों की प्रार्थना सुनकर ब्रह्माजी ने अपना दिव्य मनोमय चक्र छोड़ा। उन्होंने कहा कि यह चक्र जहां जाकर स्थिर होगा, वही भूमि कलियुग के प्रभाव से मुक्त रहेगी। ब्रह्माजी का यह चक्र आकाश में घूमता हुआ एक विशाल वन क्षेत्र में आकर रुक गया। उसी स्थान को बाद में नैमिषारण्य के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि चक्र के रुकते ही वहां दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ और वह क्षेत्र देवताओं, ऋषियों तथा तपस्वियों की साधना भूमि बन गया। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु इस स्थान को आध्यात्मिक सुरक्षा और दिव्यता का केंद्र मानते हैं।

नैमिषारण्य का उल्लेख केवल एक-दो ग्रंथों में नहीं, बल्कि अनेक प्रमुख धर्मग्रंथों में मिलता है। महाभारत, रामायण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण और अन्य अनेक धार्मिक ग्रंथ इसकी महिमा का वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में यह एक विशाल वन क्षेत्र था, जहां ऋषि-मुनि वर्षों तक तपस्या करते थे। मान्यता है कि यहां 88 हजार ऋषियों ने एक साथ बैठकर धर्म, ज्ञान और मोक्ष के विषय में विचार-विमर्श किया था। यही वह स्थान है जहां सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को पुराणों का ज्ञान सुनाया था। इस दृष्टि से नैमिषारण्य केवल तीर्थ ही नहीं, बल्कि सनातन ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र भी है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार इस क्षेत्र में 33 कोटि देवी-देवताओं का निवास है। कहा जाता है कि देवता समय-समय पर यहां आकर तपस्या और यज्ञों में भाग लेते रहे हैं। इस कारण यहां की भूमि को देवभूमि का दर्जा प्राप्त है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां किया गया जप, तप, दान, हवन और पूजा अन्य स्थानों की अपेक्षा कई गुना अधिक फलदायी होती है। यही कारण है कि पूरे वर्ष यहां भक्तों का आगमन बना रहता है।

नैमिषारण्य का सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख तीर्थ चक्रतीर्थ है। यह वही स्थान माना जाता है जहां ब्रह्माजी का मनोमय चक्र आकर गिरा था। वर्तमान में यहां एक गोलाकार कुंड स्थित है, जिसके केंद्र से निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। इस कुंड का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहां स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि की कामना करते हैं। यह विश्वास है कि चक्रतीर्थ में स्नान करने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसके जीवन की अनेक बाधाएं दूर हो जाती हैं। नैमिषारण्य का संबंध भगवान विष्णु से भी अत्यंत गहरा माना जाता है। कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने इस क्षेत्र को विशेष रूप से धर्म और तपस्या की रक्षा के लिए चुना था। यही कारण है कि यहां विष्णु भक्ति की परंपरा भी अत्यंत प्राचीन है। अनेक वैष्णव संतों ने इस भूमि को मोक्षदायिनी बताया है। कहा जाता है कि यहां भगवान विष्णु की उपासना करने से भक्त को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है और उसके जीवन में धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ती है।

इस पवित्र क्षेत्र का संबंध भगवान श्रीराम से भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लंका विजय और अयोध्या वापसी के बाद भगवान श्रीराम ने यहीं अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया था। अश्वमेध यज्ञ केवल राजसत्ता का प्रतीक नहीं था, बल्कि धर्म, न्याय और लोककल्याण की स्थापना का संदेश भी देता था। श्रीराम के इस यज्ञ के कारण नैमिषारण्य की पवित्रता और महत्व में और अधिक वृद्धि हुई। रामभक्तों के लिए यह स्थान विशेष श्रद्धा का केंद्र माना जाता है।

नैमिषारण्य की महिमा महर्षि दधीचि की कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवताओं के लिए उनका सामना करना कठिन हो गया, तब महर्षि दधीचि ने धर्म और लोककल्याण की रक्षा के लिए अपना शरीर तक समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी अस्थियां देवराज इन्द्र को दान कर दीं, जिनसे वज्र का निर्माण हुआ और वृत्रासुर का वध संभव हो सका। त्याग और बलिदान की यह अनुपम कथा आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। नैमिषारण्य में स्थित दधीचि आश्रम इस महान ऋषि की स्मृतियों को जीवित रखे हुए है।

नैमिषारण्य में स्थित ललिता देवी मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। इसे देवी शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां ललिता देवी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के दौरान यहां विशेष उत्सव आयोजित होते हैं और हजारों भक्त देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण भक्तों को अद्भुत शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यहां व्यास गद्दी, हनुमान गढ़ी, सीता कुंड, पंचप्रयाग, दधीचि कुंड और अन्य अनेक पवित्र स्थल स्थित हैं। प्रत्येक स्थान किसी न किसी पौराणिक घटना और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। श्रद्धालु इन स्थलों के दर्शन कर स्वयं को धर्म और संस्कृति की गौरवशाली विरासत से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। नैमिषारण्य की एक विशेष पहचान इसकी प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा है। यह परिक्रमा अत्यंत कठिन और पुण्यदायी मानी जाती है। फाल्गुन मास में हजारों श्रद्धालु इस परिक्रमा में भाग लेते हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक 84 कोसी परिक्रमा करने से मनुष्य को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह परिक्रमा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, अनुशासन और भक्ति का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि यदि कोई साधक इस पवित्र भूमि पर बारह वर्षों तक तपस्या करे तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो सकती है। यह मान्यता इस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है। सदियों से अनेक संत, योगी और तपस्वी यहां साधना करते रहे हैं। आज भी यहां ध्यान और योग के माध्यम से आत्मिक शांति की खोज करने वाले लोगों की कमी नहीं है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

GSV बन रहा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का नया राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, आगामी VGRC में वैश्विक मंच पर चमकेगी वडोदरा की पहचान

- देश की पहली और एकमात्र परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स केंद्रित केंद्रीय विश्वविद्यालय है GSV
- 23+ राज्यों के 1,000 से अधिक छात्र, राष्ट्रीय स्तर के इस शैक्षणिक इकोसिस्टम का हिस्सा बने
- 60+ प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ उद्योग साझेदारी, 89% से अधिक प्लेसमेंट रिकॉर्ड
- रेलवे, एविएशन, मैरीटाइम, AI और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर फोकस

गांधीनगर : भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे समय में कुशल मानव संसाधन तैयार करना सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। इसी दिशा में केंद्र सरकार के मार्गदर्शन और गुजरात सरकार के सहयोग से 6 दिसंबर 2022 को वडोदरा में स्थापित गति शक्ति विश्वविद्यालय (GSV) देश की पहली और एकमात्र परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स केंद्रित केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है।

आगामी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) के परिप्रेक्ष्य में भी GSV वडोदरा की उभरती शैक्षणिक उत्कृष्टता, नवाचार क्षमता और उद्योग-संचालित कौशल विकास मॉडल का एक सशक्त उदाहरण बनकर सामने आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसी संस्थागत उपलब्धियों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा, जिससे वडोदरा की पहचान ज्ञान, नवाचार और निवेश के उभरते केंद्र के रूप में और मजबूत होगी।

इंडस्ट्री ड्रिवन मॉडल: जहां शिक्षा सीधे जुड़ती है रोजगार से

वडोदरा के लालबाग क्षेत्र में स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उद्योग, अनुसंधान और नवाचार को एक साथ जोड़ने वाली "इंडस्ट्री ड्रिवन एंड इनोवेशन लेड" संस्था के रूप में विकसित हो रहा है। यहां रेलवे, एविएशन, मैरीटाइम, रोड एवं हाईवे, मेट्रो रेल, सप्लाई चेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में विश्वस्तरीय पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को वैश्विक करियर के लिए तैयार किया जाता है।

विश्वविद्यालय परिसर आधुनिक कक्षाओं, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, अनुसंधान केंद्रों, छात्रावासों तथा उद्योग आधारित प्रशिक्षण सुविधाओं से सुसज्जित है। लालबाग स्थित वर्तमान परिसर के अतिरिक्त वाघोडिया (वडोदरा) में एक नए परिसर की स्थापना की प्रक्रिया भी जारी है।

23 से अधिक राज्यों के छात्र, राष्ट्रीय स्तर का शैक्षणिक इकोसिस्टम

वर्तमान में देश के 23 से अधिक राज्यों के 1,000 से ज्यादा छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टोरल स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। यह संस्थान परिवहन और लॉजिस्टिक्स शिक्षा के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम केंद्र सरकार की PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति से जुड़े हुए हैं, जो देश के विकास में प्रत्यक्ष योगदान देते हैं।

AI से एविएशन तक: भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही नई पीढ़ी

गति शक्ति विश्वविद्यालय में B.Tech, M.Tech, MBA और Ph.D. सहित अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिनमें परिवहन और लॉजिस्टिक्स पर विशेष ध्यान दिया जाता है। AI एवं डेटा साइंस से लेकर एविएशन इंजीनियरिंग और मैरीटाइम इंजीनियरिंग तक के कार्यक्रम नई पीढ़ी को तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर रहे हैं।

साथ ही, विश्वविद्यालय हर वर्ष भारतीय रेलवे, रक्षा बलों तथा मित्र देशों के 1,100 से अधिक अधिकारियों को विशेष कार्यकारी प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

क्लासरूम से आगे, लाइव प्रोजेक्ट्स और हैंड्स-ऑन लर्निंग पर जोर

GSV की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। छात्रों को भारतीय रेलवे के केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों, उद्योग इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स और हैंड्स-ऑन लर्निंग के माध्यम से व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है। इससे छात्रों को वास्तविक औद्योगिक चुनौतियों को समझने और उनका समाधान विकसित करने का अवसर मिलता है।

एयरबस, DRDO, अमेज़न और सिमेन्स जैसे वैश्विक साझेदारों का भरोसा

"नवाचार आधारित और उद्योग आधारित" दृष्टिकोण के तहत विश्वविद्यालय ने एयरबस, प्लासर, L&T, DGCA, सिमेन्स, अमेज़न, DRDO, SAP, CII, नोकिया, DFCCIL, CONCOR, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा मोनाश यूनिवर्सिटी जैसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ मजबूत साझेदारी स्थापित की है।

एयरबस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल अनुसंधान, AI आधारित परिवहन प्रणालियां, स्मार्ट मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स जैसे प्रोजेक्ट्स पर विशेष कार्य किया जा रहा है। कई पेटेंट और स्टार्टअप्स के माध्यम से "आत्मनिर्भर भारत" के विजन को भी गति दी जा रही है।

राष्ट्रपति सम्मान से अंतरराष्ट्रीय सहयोग तक, शोध में नई पहचान

यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. वेंकट चिंतला को सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में नई तकनीकों के विकास के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति सुश्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के ट्रांसपोर्ट फॉर न्यू साउथ वेल्स के साथ हाल ही में हुए समझौते ने परिवहन और लॉजिस्टिक्स अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत किया है। विश्वविद्यालय ने नवाचार, स्टार्टअप्स और एप्लाइड रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त इन्क्यूबेशन एवं उद्यमिता इकोसिस्टम भी विकसित किया है।

89% प्लेसमेंट और 60+ कंपनियां: करियर निर्माण का मजबूत प्लेटफॉर्म बन रही GSV

रोजगार और प्लेसमेंट के क्षेत्र में भी GSV ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। विश्वविद्यालय के करियर डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से 60 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट में भाग ले चुकी हैं, जिनमें सिमेन्स, अल्स्टॉम, टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग, L&T, हिटाची, मर्स्क, NYK ग्रुप, जिंदल स्टेनलेस, JSW, इंडिकोल्ड, DFCCIL, RITES और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियां शामिल हैं। पिछले दो वर्षों में विश्वविद्यालय ने 2025 में 91 प्रतिशत और 2026 में 89 प्रतिशत का उत्कृष्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड दर्ज किया है।

'विकसित भारत @2047' के लिए तैयार हो रहा ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का नया नेतृत्व

गति शक्ति विश्वविद्यालय एक अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान के रूप में स्थापित हो चुका है, जो उद्योग-अकादमिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार कर रहा है तथा 'विकसित भारत @2047' के राष्ट्रीय विजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

आगामी VGRC में वडोदरा बनेगा निवेश, शिक्षा और नवाचार का उभरता वैश्विक केंद्र

इस तरह से गति शक्ति विश्वविद्यालय जैसे संस्थान वडोदरा की बढ़ती शैक्षणिक और औद्योगिक क्षमता को नई पहचान दे रहे हैं। ऐसे में वडोदरा में आयोजित होने वाला आगामी VGRC राज्य की इन उपलब्धियों को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है। यह सम्मेलन निवेश, नवाचार और ज्ञान-आधारित विकास को नई गति देते हुए वडोदरा को देश के उभरते लॉजिस्टिक्स, शिक्षा और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

वेरावल-राजकोट लोकल ट्रेनों में अस्थायी रूप से लगाए जाएंगे 2 अतिरिक्त जनरल कोच

यात्रियों की सुविधा तथा बढ़ती हुई यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे ने वेरावल–राजकोट एवं राजकोट–वेरावल लोकल ट्रेनों में अस्थायी रूप से अतिरिक्त जनरल कोच लगाने का निर्णय लिया है।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार अतिरिक्त कोचों का विवरण निम्नानुसार है –

ट्रेन संख्या 59421 राजकोट–वेरावल लोकल में दिनांक 02 जून 2026 से 01 अगस्त 2026 तक 02 अतिरिक्त जनरल कोच लगाए जाएंगे।

ट्रेन संख्या 59422 वेरावल–राजकोट लोकल में दिनांक 03 जून 2026 से 02 अगस्त 2026 तक 02 अतिरिक्त जनरल कोच लगाए जाएंगे।

मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर श्री दिनेश वर्मा ने बताया कि उक्त व्यवस्था लागू होने के बाद इन ट्रेनों में वर्तमान 09 जनरल कोचों के स्थान पर कुल 11 जनरल कोच उपलब्ध रहेंगे और इससे यात्रियों को यात्रा करने में सुविधा प्राप्त होगी। इस निर्णय से लम्बे समय से लंबित यात्रियों की माँग पूर्ण हुई है।

पश्चिम रेलवे यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

यात्रीगण ट्रेनों के परिचालन एवं अन्य विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर के बीच चलाएगी नॉनस्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा बांद्रा टर्मिनस एवं जयपुर स्टेशनों के बीच विशेष किराये पर नॉनस्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09708/09707 बांद्रा टर्मिनस–जयपुर नॉनस्टॉप सुपरफास्ट स्पेशल (8 फेरे)

ट्रेन संख्या 09708 बांद्रा टर्मिनस–जयपुर स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को 15:50 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 08:45 बजे जयपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन 04 जून, 2026 से 25 जून, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09707 जयपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक बुधवार को 19:40 बजे जयपुर से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 14:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 03 जून, 2026 से 24 जून, 2026 तक चलेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी–2 टियर, एसी–3 टियर, एसी–3 टियर (इकोनॉमी) तथा स्लीपर क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09708 की बुकिंग दिनांक 31.05.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों एवं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव एवं संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं।

भीषण गर्मी के बीच महंगी हुई बिजली, जून से उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा अतिरिक्त भार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई के बीच अब बिजली उपभोक्ताओं को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। भीषण गर्मी के मौसम में जहां बिजली की खपत अपने चरम पर पहुंच जाती है, वहीं जून माह से बिजली बिलों में 10 प्रतिशत अतिरिक्त ईंधन अधिभार लगाए जाने के फैसले ने लाखों परिवारों, कारोबारियों और संस्थानों की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) द्वारा जारी आदेश के अनुसार जून से जारी होने वाले बिजली बिलों में फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस) के रूप में अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी। इसका सीधा असर घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

प्रदेश में इस समय भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग लगातार रिकॉर्ड स्तर पर बनी हुई है। तापमान बढ़ने के साथ एयर कंडीशनर, कूलर, पंखे और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग भी तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में सामान्य दिनों की तुलना में बिजली बिल पहले से ही अधिक आता है। अब बिजली विभाग द्वारा लगाए गए 10 प्रतिशत अतिरिक्त ईंधन अधिभार ने उपभोक्ताओं के मासिक खर्च में और बढ़ोतरी की आशंका पैदा कर दी है। खासकर मध्यम वर्गीय परिवारों, छोटे व्यापारियों और सीमित आय वाले उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला आर्थिक दबाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है। यूपीपीसीएल का कहना है कि बिजली उत्पादन और बिजली खरीद की लागत में लगातार वृद्धि हो रही है। प्रदेश की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य को कई बार बाहरी स्रोतों से भी बिजली खरीदनी पड़ती है। अंतरराज्यीय बिजली बाजार में बढ़ी हुई कीमतों और ईंधन लागत में वृद्धि के कारण बिजली कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा है। इसी अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए एफपीपीएएस लागू करने का निर्णय लिया गया है। बिजली कंपनियों का तर्क है कि उत्पादन और खरीद लागत में हुए बदलाव को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना नियामकीय व्यवस्था का हिस्सा है।

ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। ऐसे समय में वितरण कंपनियों को अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसकी कीमत अक्सर अधिक होती है। इसके कारण विद्युत वितरण कंपनियों पर वित्तीय दबाव बढ़ता है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि लागत का पूरा भार उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय दीर्घकालिक ऊर्जा प्रबंधन और उत्पादन क्षमता बढ़ाने जैसे उपायों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ कम किया जा सके। इस फैसले का प्रभाव केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा। छोटे और मध्यम उद्योगों, दुकानदारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सेवा क्षेत्र से जुड़े व्यवसायों तथा अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को भी अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा। कई व्यापारिक संगठनों का मानना है कि पहले से बढ़ती लागत और बाजार में प्रतिस्पर्धा के बीच बिजली शुल्क में बढ़ोतरी उनके परिचालन खर्च को प्रभावित करेगी। इसका असर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों पर भी दिखाई दे सकता है।

महंगाई से जूझ रहे आम लोगों के लिए यह फैसला ऐसे समय आया है जब पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें पहले से ही घरेलू बजट पर दबाव बनाए हुए हैं। बिजली बिल में 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार जुड़ने से परिवारों के मासिक खर्च में और वृद्धि होगी। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवार, जहां एयर कंडीशनर और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग अधिक होता है, उन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है।

पश्चिम रेलवे द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता अभियान को किया गया सशक्त

रेल परिसरों में जागरूकता कार्यक्रम, प्लास्टिक-विरोधी पहल एवं स्वच्छता अभियान आयोजित

पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2026 अभियान के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता एवं सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न पहलें संचालित की जा रही हैं। 23 से 26 मई, 2026 तक आयोजित इस अभियान में मंडल भर में रेल कर्मचारियों, विक्रेताओं, यात्रियों, गैर-सरकारी संगठनों तथा आम जनता ने सक्रिय सहभागिता निभाई।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करने तथा प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से विक्रेता स्टॉलों पर विशेष निरीक्षण अभियान चलाए गए, ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। विक्रेताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को वर्जिन प्लास्टिक उत्पादों के स्थान पर रिसाइकिल्ड विकल्प अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कमी लाने की पहल के अंतर्गत रेलवे परिसरों में स्थित लगभग 140 वॉटर रिफिल केंद्रों का निरीक्षण किया गया। यात्रियों को एकल-उपयोग प्लास्टिक बोतलों के स्थान पर अपनी पानी की बोतलों को पुनः भरकर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कई स्टेशनों पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण एवं पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार के संबंध में जागरूकता संदेश भी प्रसारित किए गए।

विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान एवं जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य डिस्पोजेबल प्लास्टिक वस्तुओं के सीमित उपयोग को बढ़ावा देना था। पर्यावरण संरक्षण तथा प्लास्टिक प्रदूषण के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु एनजीओ एवं अन्य सहभागी संगठनों के सहयोग से नुक्कड़ नाटक एवं संवादात्मक जागरूकता गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं।

मंडल द्वारा स्टेशनों एवं रेलवे परिसरों में स्वच्छता अभियान भी चलाए गए, ताकि स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर वातावरण बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया जा सके तथा हरित रेलवे वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके।

इन पहलों के माध्यम से पश्चिम रेलवे का मुंबई सेंट्रल मंडल पर्यावरणीय स्थिरता एवं जनभागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए एक स्वच्छ, हरित एवं पर्यावरण-सचेत भविष्य के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्यरत है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के नारायणा अस्पताल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर का प्रारंभ कराया

कैंसर जैसे गंभीर रोग के मरीजों को तेज एवं अधिक सटीक उपचार के लिए अत्याधुनिक 'हैल्सियन' टेक्नोलॉजी से सज्ज रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर कार्यरत हुआ

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शनिवार को अहमदाबाद स्थित नारायणा अस्पताल में नए रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर का प्रारंभ कराया।

नारायणा अस्पताल ने कैंसर के उपचार को अधिक सुलभ एवं प्रभावशाली बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

मुख्यमंत्री ने इस ऑन्कोलॉजी सेंटर की मुलाकात लेकर अस्पताल द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी प्राप्त की।

यह केंद्र 'हैल्सियन रेडिएशन थेरापी सिस्टम' से सज्ज है और यह उपचार पद्धति विशेष रूप से अद्भुत तेजी तथा सटीकता के लिए प्रसिद्ध है।

इस टेक्नोलॉजी द्वारा कैंसर की गाँठ के आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं पर होने वाले दुष्प्रभाव को नहीं के बराबर करते हुए हाई-प्रिसिजन तथा इमेज-गाइडेड उपचार प्रदान किया जाएगा।

अहमदाबाद के नारायणा अस्पताल में इस नए रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेंटर के प्रारंभ के साथ अब मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी तथा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी; तीनों विभाग उपलब्ध हुए हैं और 'इंटीग्रेटेड कैंसर केयर' उपचार संभव हुआ है।

इतना ही नहीं; अहमदाबाद तथा आसपास के जिलों के लोगों को अब कैंसर का संपूर्ण उपचार आसानी से एक ही स्थान पर मिलेगा।

इस अवसर पर नारायणा हेल्थ के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. देवी शेट्टी, फैसिलिटी डाइरेक्टर श्री हेमंत भटनागर, कन्सल्टैंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. तस्नीम नलवाला तथा गणमान्य चिकित्सक, आमंत्रित एवं अस्पताल के सेवा कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

मतदाता सूची को और शुद्ध बनाने की कवायद, एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग का भरोसा

नई दिल्ली। देश में मतदाता सूची की शुद्धता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को लेकर चल रही बहस के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग का लक्ष्य प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित करना और अपात्र नामों को सूची से व्यवस्थित रूप से हटाना है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर संचालित की जा रही है और यह न केवल कानूनी कसौटियों पर खरी उतरी है, बल्कि संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन का भी प्रभावी माध्यम साबित हुई है।

शनिवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती का आधार एक सटीक और विश्वसनीय मतदाता सूची होती है। यदि मतदाता सूची त्रुटिरहित और अद्यतन हो, तभी चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। इसी सोच के साथ निर्वाचन आयोग लगातार मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रहा है।

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत के ऐसे सभी नागरिक, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और जो कानूनन मतदान के पात्र हैं, उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसके साथ ही आयोग उन नामों की भी पहचान कर रहा है जो किसी कारणवश मतदाता सूची में बने हुए हैं, जबकि वे पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते। इनमें मृत व्यक्तियों के नाम, एक से अधिक स्थानों पर दर्ज दोहराए गए नाम, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाता, लंबे समय से अनुपस्थित लोग तथा विदेशी नागरिकों के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों की पहचान कर सूची को अधिक सटीक बनाया जा रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक अभ्यास नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती से जुड़ा महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया की निगरानी व्यापक स्तर पर की जा रही है और इसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उनके अनुसार राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के जिला तथा प्रदेश अध्यक्षों के साथ-साथ 15 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय एजेंट भी इस प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होती हैं।

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर समय-समय पर विभिन्न मंचों पर सवाल उठाए गए, लेकिन यह प्रक्रिया न्यायिक परीक्षण में भी सफल रही है। उन्होंने कहा कि एसआईआर न केवल सुप्रीम कोर्ट की जांच और परीक्षण में खरा उतरा है, बल्कि इसने निर्वाचन आयोग को अपने संवैधानिक और कानूनी दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में भी मदद की है। उनके अनुसार मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करना निर्वाचन आयोग की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है और एसआईआर इस दिशा में एक प्रभावी साधन साबित हुआ है।

उन्होंने बताया कि इस विशाल कार्य को पूरा करने के लिए देशभर में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक तंत्र सक्रिय किया गया है। वर्तमान में 11 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी इस अभियान में जुटे हुए हैं। ये सभी अधिकारी विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं, जिन्हें निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर लगाया गया है। उनका कार्य घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना, रिकॉर्ड का मिलान करना और पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने तथा अपात्र नामों को हटाने की प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से पूरा करना है।

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

संख्या: W / 623/5/1/NIT दिनांक: 27.05.2026

ई-निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक / मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा), पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल, निम्नलिखित कार्य के लिए "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेब-साईट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है। **ई टेंडरिंग संख्या: RTM-2026-27-48. कार्य का नाम**: Berchha Raising of platform no. 2. **अनुमानित लागत**: रु. 1,72,36,263.60. **बयाना राशी**: रु. 3,44,800/-. **कार्य की समापन अवधि**: 8 Months. **Similar Type of Work**: Any Civil Engineering Work. **वेब-साईट पर अपलोड करने की तिथि**: 27.05.2026. **निविदा खुलने की तिथि**: 19.06.2026. विस्तृत निविदा सूचना अर्हता शर्ते एवं अन्य शर्ते वेब-साईट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। टेंडर फॉर्म की कीमत NIL है। **SPAN/5/1/76**

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेल्वे द्वारा अहमदाबाद ⇌ पटना के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन के फेरे बढाए जाएगे

ट्रेन क्र.	से	तक	चलाने का दिन	से विस्तृत
09447	अहमदाबाद	पटना	बुधवार	03.06.2026
09448	पटना	अहमदाबाद	शुक्रवार	05.06.2026

ठहराव के समय और ट्रेन की बनावट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाएं।

ट्रेन संख्या 09447 की विस्तारित यात्राओं के लिए बुकिंग दि.31.05.2026 से PRS काउंटरों और IRCTC की वेबसाइट पर शुरू होगी। यह ट्रेन स्पेश्यल किराए पर स्पेश्यल ट्रेन के रूप में चलेगी।

पश्चिम रेलवे
wr.indianrailways.gov.in
हमें लाईक और फोलो करें
facebook.com/WesternRly
X.com/WesternRly
Instagram.com/WesternRly
https://www.youtube.com/@WesternRly
https://bit.ly/WesternRailwayOfficial

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

संख्या: W/623/5/3/NIT दिनांक: 27.05.2026

ई-निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक / मंडल कार्यालय (कार्यलेखा शाखा), पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल, निम्नलिखित कार्य के लिए "खुली निविदा" ई-निविदा के माध्यम से वेब-साईट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते हैं। विवरण इस प्रकार है। **ई टेंडरिंग संख्या: RTM-2026-27-51. कार्य का नाम**: Dahod: Construction of Running Room at DHD station. **अनुमानित मात्रा**: As per tender schedule. **अनुमानित लागत**: रु. 2,43,22,599.52. **बयाना राशी**: रु. 4,86,500/-. **कार्य की समापन अवधि**: 18 Months. **Similar Type of Work**: Construction of any Building Work. **वेब-साईट पर अपलोड करने की तिथि**: 27.05.2026. **निविदा खुलने की तिथि**: 19.06.2026. विस्तृत निविदा सूचना अर्हता शर्ते एवं अन्य शर्ते वेब-साईट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। **SPAN/5/1/77**

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

पश्चिम रेलवे - रतलाम मंडल

ई-निविदा सूचना

मंडल रेल प्रबंधक (संकेत एवं दूरसंचार), पश्चिम रेलवे, रतलाम द्वारा **निविदा संख्या: SnT-RTM - 26 Tele- 11, दिनांक: 27.05.2026** निम्न कार्य के लिए आमंत्रित की जाती हैं। **कार्य का नाम**: **रतलाम मंडल**: DRM कार्यालय परिसर में MPLS NOC सहित दूरसंचार अवसंरचना के संवर्धन, उन्नयन तथा दूरसंचार उपकरणों के प्रतिस्थापन द्वारा विश्वसनीयता सुधार के संबंध में दूरसंचार सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग। **कार्य की अनुमानित लागत**: रु. 3,79,37,798.84. **निविदा प्रपत्र का मूल्य**: शून्य। **जमानत राशि**: रु. 7,58,800/-. **कार्य पूर्ण करने की अवधि**: बारह (12) माह। **ई-निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि व समय**: दिनांक 30.06.2026 समय 15:00 बजे तक। **ई-निविदा खोलने की तिथि व समय**: दिनांक 30.06.2026 समय 15:30 बजे तक। **वैधता**: निविदा खुलने की दिनांक से 60 दिन। निविदा **www.ireps.gov.in** वेबसाइट पर देखी जा सकती है। **SPAN/6/1/78**

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly

गुजरात के राहुल जाखड़ ने एशियन यू-20 डेकाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा

वापी के मैदान से एशिया के पोडियम तक की यात्रा, वलसाड के 18 वर्षीय खिलाड़ी ने हांगकांग में बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

> "मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल-कूद का मजबूत ढाँचा तैयार किया है और विश्व स्तरीय सुविधाएँ विकसित की हैं। युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हर संभव सुविधा देने का हमारा संकल्प है। राहुल को प्राप्त उपलब्धि इन प्रयासों का ही परिणाम है।"
>
> **– उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी**

गांधीनगर : वापी के एक स्थानीय मैदान में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण लेते हुए देखकर उत्सुकता से शुरू हुई यात्रा आज भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखी गई है। गुजरात के वलसाड जिले के चरवाडा गाँव के 18 वर्षीय राहुल जाखड़ ने हांगकांग (चीन) में आयोजित 22वीं एशियन यू-20 (अंडर-20) एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में डेकाथलॉन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है।

राहुल ने दस इवेंट की इस कठिन प्रतियोगिता में कुल 7,185 पॉइंट्स प्राप्त कर खिताब अपने नाम किया और साथ ही अंडर-20 श्रेणी में भारत का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया।

यह उपलब्धि केवल राहुल के लिए ही नहीं, बल्कि भारतीय एथलेटिक्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के समान है। इस प्रदर्शन के साथ राहुल एशिया के श्रेष्ठ यू-20 डेकाथलिट बने हैं और उनन्होंने वैश्विक क्रम में भी शीर्ष के आठ खिलाड़ियों में स्थान हासिल किया है।

मूलतः राजस्थान के सीकर जिले के निवासी और 30 वर्ष पहले वलसाड जिले के वापी में स्थायी होकर निर्माण (कन्स्ट्रक्शन) व्यवसाय से जुड़े परिवार के पुत्र राहुल की यह सफलता प्रतिभा, संकल्प एवं अथक परिश्रम की प्रेरणादायी गाथा है।

राहुल जाखड़ के कोच के अनुसार राहुल की यह सफलता वर्षों की मेहनत,

वैज्ञानिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञ मार्गदर्शन तथा गुजरात में विकसित हो रहे खेल-कूद के मजबूत ढाँचे का परिणाम है।

हांगकांग से फोन पर बात करते हुए राहुल ने कहा, "मेरी समग्र यात्रा में मुझे मार्गदर्शन तथा सहयोग देने वाले मेरे सभी कोच का मैं आभारी हूँ। गुजरात सरकार ने खिलाड़ियों को उत्तम सुविधाएँ एवं अवसर प्रदान किए हैं। अब मेरा सपना कॉमनवेल्थ गेम्स तथा ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का है और इसके लिए मैं लगातार मेहनत करता रहूंगा।"

राहुल की उपलब्धि का महत्व समझाते हुए उनके एक्सपर्ट एथलेटिक कोच शिवम उपाध्याय ने कहा कि डेकाथलॉन एथलेटिक्स की सबसे कठिन स्पर्धाओं में एक मानी जाती है। इसमें खिलाड़ी को 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, शॉटपुट, ऊँची कूद, 400 मीटर दौड़, 110 मीटर हर्डल्स, डिस्क्स थ्रो, पोल वोल्ट, जेवलीन थ्रो तथा 1500 मीटर दौड़ सहित कुल दस इवेंट में श्रेष्ठ प्रदर्शन करना पड़ता है। उन्होंने कहा, "राहुल ने 7,185 पॉइंट अर्जित कर रेकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन किया है और स्वर्ण पदक जीता है। अब अंडर-20 श्रेणी में भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड उसके नाम पर है।"

हाल ही में कक्षा 11 की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले राहुल जाखड़ इस समय स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गुजरात (एसएजी) के नडियाद स्थित हाई-परफॉर्मेंस सेंटर (एचपीसी) में प्रशिक्षण ले रहे हैं, जहाँ उन्हें अत्याधुनिक कोचिंग का सहयोग मिल रहा है।

उप मुख्यमंत्री एवं खेल-कूद मंत्री श्री हर्ष संघवी ने राहुल को अभिनंदन देते हुए कहा कि उनकी मेहनत तथा राज्य सरकार द्वारा खेल-कूद क्षेत्र में किए गए निवेश के परिणामस्वरूप ऐसी प्रतिभाएँ विकसित हो रही हैं।

श्री संघवी ने कहा, "मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए मजबूत खेल-कूद ढाँचा और विश्व स्तरीय सुविधाएँ विकसित की हैं। युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हर संभव अवसर देने का हमारा संकल्प है। राहुल की उपलब्धि इन्हीं प्रयासों का परिणाम है।"

उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के लिए गुजरात में चल रही तैयारियों के हिस्से के रूप में विश्व स्तरीय खेल-कूद सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं, जो भविष्य के खिलाड़ियों के लाभदायी सिद्ध होंगी।

नडियाद स्थित एचपीसी गुजरात के अग्रगण्य खेल-कूद संस्थानों में एक है। इस आवासीय केंद्र में 200 से अधिक खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में विशेष कोचिंग, स्पोर्ट्स साइंस सहायता और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

एक संयोग, जिसने जीवन बदल डाला

राहुल की एथलेटिक्स की यात्रा एक अप्रत्याशित संयोग से शुरू हुई थी। कुछ वर्ष पहले वे अपने पिता के साथ वापी में शाम को घूमने के लिए निकले थे, तब उन्होंने स्थानीय मैदान में कुछ खिलाड़ियों को प्रशिक्षण लेते देखा। उत्सुकतावश उन्होंने पूछा कि वे लोग क्या कर रहे हैं।

राहुल जाखड़ उस प्रसंग को याद करते हुए कहते हैं, "मैदान में दौड़ रहे लोगों ने मुझसे कहा कि वे स्पर्धाओं की तैयारी करने वाले एथलीट्स हैं। अगले ही दिन मैं भी उसी मैदान में दौड़ने लगा, कारण कि मुझे एथलीट बनना था।"

इसके बाद राहुल ने अपने स्कूल की ओर से खेल महाकुंभ में भाग लिया और लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत ने उनके मन में एथलेटिक्स के प्रति उत्साह जगाया और उन्होंने इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प किया।

जो किशोर कभी मैदान के किनारे खड़ा रहकर प्रशिक्षु खिलाड़ियों को देखता था, आज वही एशिया के विजेता मंच पर खड़ा रहकर भारतीय एथलेटिक्स की आशाओं को नई ऊँचाई दे रहा है और ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देख रहा है।

ग्रासरूट्स से ग्लोबल मंच तक

राहुल जाखड़ ने अपने एथलेटिक्स कॅरियर की शुरुआत बनासकाँठा जिले के गढ में स्थित डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल (डीएलएसएस) में कोच विपुल चौधरी के मार्गदर्शन में की थी। उनकी प्रतिभा को पहचान कर वर्ष 2024 में उनका नडियाद स्थित एचपीसी में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया।

कोच शिवम उपाध्याय, धर्मेन्द्र प्रधान तथा सतेश उपाध्याय के मार्गदर्शन में राहुल ने डेकाथलॉन तथा अन्य संयुक्त इवेंट्स में लगातार उत्तम प्रदर्शन किया और धीरे-धीरे एक आशावान एथलीट के रूप में अपनी पहचान स्थापित की।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल द्वारा जिला प्रशासनों को राज्य 'स्वागत' अंतर्गत आने वाली शिकायतों का समयसीमा में न्यायिक एवं सरलतापूर्वक निवारण लाकर जनता का सरकार के प्रति विश्वास अधिक सुदृढ़ करने के स्पष्ट दिशा-निर्देश

- **मुख्यमंत्री ने मई-2026 के राज्य स्तरीय 'स्वागत' ऑनलाइन शिकायत निवारण कार्यक्रम में प्रसुत्तियाँ-शिकायतें लेकर आए किसानों तथा आम आदमी की प्रस्तुतियाँ संवेदनापूर्वक सुनकर त्वरित निवारण के निर्देश दिए**
- **राज्य, जिला तथा तहसील 'स्वागत' में समग्रतः 4020 आवेदकों की प्रस्तुतियाँ सम्बद्ध विभागों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी गईं**
- **मुख्यमंत्री का पुलिस प्रशासन को सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ाई से पेश आकर किसानों को सुरक्षा की अनुभति कराने का निर्देश**

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिला प्रशासनों को राज्य 'स्वागत' अंतर्गत आने वाली प्रस्तुतियों-शिकायतों का समयसीमा में न्यायिक एवं सरलतापूर्वक निवारण लाकर जनता का सरकार के प्रति विश्वास अधिक सुदृढ़ हो; इस तरह कार्य करने के दिशा-निर्देश दिए हैं।

इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि किसी भी प्रस्तोता का कार्य नियमानुसार होने योग्य हो, तो तत्काल उसे पूरा करके देना चाहिए। इतना ही नहीं; यदि नियमानुसार कार्य न हो सकने वाला हो, तो सम्बद्ध व्यक्ति को बार-बार कार्यालय के चक्कर लगवाने के बदले तत्काल तथा स्पष्ट उत्तर दे देना-भेज देना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को मई-2026 के राज्य स्तरीय 'स्वागत' ऑनलाइन जन शिकायत निवारण कार्यक्रम में प्रत्यक्ष प्रस्तुतियाँ लेकर आए सभी आम लोगों की प्रस्तुतियाँ संवेदनापूर्वक सुनीं।

सामान्यतः हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित होने वाला यह राज्य 'स्वागत' कार्यक्रम इस बार मई के चौथे गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण शनिवार को आयोजित हुआ।

इस राज्य 'स्वागत' में 215 से अधिक आवेदक अपनी प्रस्तुतियों के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय की जनसंपर्क इकाई में उपस्थित रहे। जिला 'स्वागत' में 1531 तथा तहसील 'स्वागत' में 2274 सहित समग्रतः 4020 आवेदकों की प्रस्तुतियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बद्ध विभागों को भेज दिया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष इस राज्य 'स्वागत' में जूनागढ, भावनगर तथा गिर सोमनाथ जिलों के किसानों ने अपने खेतों के आवागमन मार्ग पर हुए अवैध अतिक्रमणों को लेकर शिकायत की।

मुख्यमंत्री ने किसानों की शिकायतों को लेकर सम्बद्ध जिला प्रशासनों को निर्देश देकर सार्वजनिक मार्गों पर ऐसे अतिक्रमण न हों और किसान अपने कृषि संसाधन एवं उत्पाद आसानी से ले जा सकें, इसके लिए मार्ग अतिक्रमणुमुक्त रहें; यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध

कड़ाई से काम लेकर किसानों को सुरक्षा की अनुभूति कराने का निर्देश दिया।

बोटाद जिले के एक आवेदक की कृषि भूमि में भू-स्वामी के जीवनकाल में ही उत्तराधिकार के अधिकार दर्ज करने और उत्तराधिकार निर्मूलन की प्रविष्टि प्रमाणित करने के मामले में पूर्व में हुई प्रशासनिक भूल के कारण आवेदक पर स्टाम्प ड्यूटी का बोझ न पड़े; इसके लिए जिला प्रशासन को लोकाभिमुख दृष्टिकोण दिखाते हुए उचित कार्यवाही करने का त्वरित निर्देश दिया।

अहमदाबाद जिले के किसानों द्वारा रिसर्वे के बाद 7/12 के भूमि रिकॉर्ड अनुपलब्ध हो जाने की शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर को तत्काल कार्यवाही करने और रिसर्वे नंबर में गलती से दर्ज प्रविष्टि के सुधार के लिए भी आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि भूमि रिकॉर्ड जनरेट करने का आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है। उन्होंने ऐसी छोटी समस्याओं का निवारण स्थानीय स्तर से ही तेजी से लाने का जिला अधिकारियों को निर्देश दिए।

वडोदरा जिले के एक आवेदक ने ग्राम-स्थल की संपत्ति की सत्यापित प्रति तथा मापन को लेकर प्रस्तुति की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सरकार के कार्यालय में रिकॉर्ड उपलब्ध न हो, लेकिन आवेदक के पास सत्यापित प्रति हो, तो उसकी उचित जाँच कर उसे मान्य मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर को जरूरी निर्देश दिए।

अरवल्ली जिले के एक गाँव का नगर पालिका में विलय होने के बाद विकास योजना मंजूर न होने के कारण आवासीय निर्माण का आज्ञा पत्र देने में विलंब होने की प्रस्तुति पर मुख्यमंत्री ने नगर पालिका को आवश्यक कार्यवाही के बाद निर्माण कार्य आज्ञा पत्र देने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य 'स्वागत' में आई सभी प्रस्तुतियों में जनहितकारी संवेदना दिखाते हुए त्वरित निवारण संबंधी दृष्टिकोण दर्शाकर प्रो-पीपल गवर्नेंस की अनुभूति कराई।

इस राज्य 'स्वागत' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, डॉ. अजय कुमार तथा विशेष कार्याधिकारी श्री धीरज पारेख व श्री राकेश व्यास और सम्बद्ध विभागों के वरिष्ठ सचिव उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री के समक्ष आई प्रस्तुतियों के संदर्भ में सम्बद्ध जिला कलेक्टर तथा प्रशासनकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े और उन्होंने पूरक विवरण तथा जानकारी प्रदान की।

फोस्टा चुनाव की सरगर्मियां तेज, मतदाता सूची परीक्षण के बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित

सूरत। फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन (फोस्टा) के आगामी चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। शनिवार को फोस्टा कार्यालय में आयोजित चुनाव अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की समीक्षा की गई और विस्तृत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। बैठक में मतदाता सूची के परीक्षण से लेकर नामांकन, नाम वापसी, मतदान और मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही सूरत के वस्त्र व्यापार जगत में चुनावी माहौल बनने लगा है।

फोस्टा सूरत के टेक्सटाइल उद्योग और व्यापार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक मानी जाती है। हजारों व्यापारियों और विभिन्न टेक्सटाइल मार्केटों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस संस्था के चुनावों पर पूरे वस्त्र उद्योग की नजर रहती है। आगामी चुनाव को लेकर भी व्यापारिक समुदाय में उत्सुकता बनी हुई है, क्योंकि चुनी जाने वाली नई टीम आने वाले वर्षों में

टेक्सटाइल व्यापार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर नेतृत्व प्रदान करेगी।

बैठक के दौरान चुनाव अधिकारियों ने 30 अप्रैल 2026 तक सदस्यता प्राप्त करने वाले सभी सदस्यों की मतदाता सूची का विस्तृत परीक्षण किया। विभिन्न टेक्सटाइल मार्केटों से प्राप्त मतदाता सूचियों का भी गहन अध्ययन किया गया ताकि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। अधिकारियों ने सदस्यता रिकॉर्ड, मतदाता पात्रता और संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा करते हुए मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी की।

चुनाव प्रक्रिया के तहत नामांकन कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार 4 जून से 6 जून 2026 तक फोस्टा कार्यालय से नामांकन पत्र प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिखित आवेदन प्रस्तुत कर नामांकन पत्र हासिल करना होगा।

नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 8 जून 2026 तय की गई है। उसी दिन शाम 6 बजे तक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र चुनाव अधिकारियों के समक्ष जमा कर सकेंगे। इसके बाद 9 जून को प्राप्त सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। चुनाव अधिकारी उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और पात्रता संबंधी शर्तों की समीक्षा करेंगे। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन शाम 6 बजे के पश्चात पात्र उम्मीदवारों की प्रारंभिक सूची फोस्टा कार्यालय में प्रकाशित की जाएगी।

चुनाव प्रक्रिया में उम्मीदवारों को नाम वापस लेने का अवसर भी दिया जाएगा। इसके लिए 13 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान यदि कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो वह अपना नामांकन वापस ले सकेगा। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम उम्मीदवार सूची तैयार की जाएगी और उसी दिन शाम 6 बजे के बाद इसे फोस्टा कार्यालय में प्रदर्शित किया जाएगा।

चुनाव अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होता है और मतदान की आवश्यकता पड़ती है, तो चुनाव 20 जून 2026 को आयोजित किए जाएंगे। मतदान का समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। मतदान स्थल के रूप में रिंग रोड स्थित Millennium Textile Market को चुना गया है, जहां सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार शाम 6 बजे से मतों की गिनती प्रारंभ होगी और मतगणना पूरी होने के बाद परिणामों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं।

फोस्टा के चुनावों को सूरत के टेक्सटाइल उद्योग के लिए विशेष महत्व का माना जाता है। संस्था व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं, सरकारी नीतियों, कराधान, आधारभूत सुविधाओं, बाजार विकास और उद्योग से जुड़े अन्य मुद्दों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। ऐसे में नई कार्यकारिणी के चयन को लेकर व्यापारिक समुदाय में विशेष रुचि देखी जा रही है।

बैठक में चुनाव अधिकारियों ने सभी सदस्यों से चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि संस्था की मजबूती उसके सदस्यों की भागीदारी और लोकतांत्रिक परंपराओं के पालन पर निर्भर करती है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव फोस्टा की गरिमा और विश्वसनीयता को और मजबूत करेंगे।

बैठक में चुनाव अधिकारी अशोक जैन, बृजमोहन अग्रवाल तथा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया और यह भरोसा जताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर ली जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही अब सूरत के टेक्सटाइल व्यापार जगत में संभावित उम्मीदवारों और विभिन्न व्यापारिक समूहों के बीच गतिविधियां तेज होने की संभावना है।

गुजरात में शिक्षकों का शोषण? शिक्षण सहायकों को दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के बराबर वेतन दिया जाता है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारत का संविधान राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में यह भी कहता है कि श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है, लेकिन क्या गुजरात में सरकार स्वयं श्रमिकों का शोषण कर रही है? गुजरात में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ केवल बाड़ें कीचड़ से सनी हैं और केवल चौकीदार ही चोरी कर रहे हैं।

भाजपा सरकार और मोदी शब्दों के साथ खेलने में माहिर हैंः तो उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया शब्द गढ़ा है और वो है 'कर्म योगी'? वे इन कर्म योगियों से कर्म करवाते हैं और उन्हें उस कर्म को योग समझने के लिए कहते हैं? सरकार ने उन्हें नियमों के अनुसार मिलने वाला मुआवजा न देने का फैसला किया है। सरकार ऐसा करती है और इसे सुशासन कहती है।

एक प्राथमिक शिक्षक, जो वेतन आयोग के नियमों के अनुसार वेतन पाने का पात्र है, उसे 2500 रुपये का शिक्षक माना जाता है। लगभग एक दशक तक, विद्या सहायक कहलाने वाले शिक्षकों का वेतन 2500 रुपये पर स्थिर रहा। राज्य मंत्रियों और विधायकों के वेतन और भत्ते बढ़े, जो कभी-कभी लगभग 55000 रुपये तक पहुंच गए। लेकिन विद्या सहायकों के वेतन में वृद्धि नहीं हुई। फिर लगभग दस साल बाद, उनका (विद्या सहायकों का) वेतन 4500 रुपये हो गया और अब यह 5300 रुपये है। इस प्रकार, एक शिक्षक को प्रतिदिन 170 रुपये की मजदूरी मिलती है। एनआरईजीए के तहत काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर को प्रतिदिन 147 रुपये की मजदूरी मिलती है। तो क्या दिहाड़ी मजदूर शिक्षकों को प्रतिदिन केवल 30 रुपये अधिक मिलते हैं? कई शिक्षण सहायक न केवल स्नातक या पीटीसी स्नातक हैं, बल्कि उन्होंने स्नातकोत्तर, एम.फिल और पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त की है। यानी, अगर गुजरात सरकार 12वीं कक्षा के बाद तीन, पांच या सात-आठ साल तक पढ़ाई करने वाले व्यक्ति को पांच साल तक दिहाड़ी मजदूर के बराबर मजदूरी देती है, तो क्या इसे सुशासन कहा जा सकता है?

अगर कोई प्लंबर नल लगाने या ठीक करने के लिए घर आता है, तो वह आधे घंटे के काम के लिए 200 रुपये लेता है। इलेक्ट्रीशियन तो इससे भी ज़्यादा लेता है। एक आम राजमिस्त्री भी छह घंटे के काम के लिए 700 से 1000 रुपये कमाता है। लेकिन गुजरात में एक शिक्षक को सिर्फ़ 177 रुपये मिलते हैं? समझे, इसे ही तो विकास कहते हैं!

यह सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का मामला है। लेकिन गुजरात सरकार द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के निजीकरण की स्थिति बेहद खराब है। आत्मनिर्भर स्कूलों में हजारों शिक्षकों को अभी भी 1500 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता है। कई स्कूलों में जूनियर केजी, सीनियर केजी और कक्षा चार या पांच तक के शिक्षकों को भी इतना ही या इससे थोड़ा अधिक वेतन मिलता है। ऐसे में वे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? और उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए? यह जनता को सोचने की जरूरत है।

सूरत जोन-3 में 19.79 लाख रुपये की शराब और बीयर नष्ट की गई, पांच पुलिस थानों से जब्त की गई वस्तुओं पर रोड रोलर चलाया गया

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत में, जोन-3 के पांच पुलिस थानों में शराबबंदी के उल्लंघन के तहत जब्त की गई 19 लाख रुपये से अधिक की शराब और बीयर को नष्ट कर दिया गया। कतरगाम पुलिस स्टेशन, महिधरपुरा पुलिस स्टेशन, लालगेट पुलिस स्टेशन, चौक बाजार पुलिस स्टेशन और सिंगनपुर पुलिस स्टेशन द्वारा जब्त की गई शराब को 20 मई को सिंगनपुर में दाभोली अक्षरवाड़ी फार्म के पास दाभोली पुल के नीचे एक रोलर चलाकर नष्ट किया गया। जब्त की गई शराब में 291 छोटी और बड़ी शराब की बोतलें और 265 बीयर के टिन शामिल थे, जिनकी कुल कीमत 1979298 रुपये थी। यह गांधी जी के गुजरात में शराबबंदी का क्रियान्वयन है।

मासूम की चीख को मिला न्याय, साढ़े पांच महीने में दोषी को उम्रकैद की सजा

गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में चार वर्ष की मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य दुष्कर्म मामले में अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है, जिसे त्वरित न्याय की एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी रामनीत देवनंदन रामरूप यादव को दोषी करार दिया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। घटना के केवल साढ़े पांच महीने के भीतर आए इस फैसले ने न केवल पीड़ित परिवार को राहत दी है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले जघन्य अपराधों के मामलों में कानून तेजी और कठोरता दोनों के साथ कार्रवाई कर सकता है।

अदालत ने अपने फैसले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा देने के साथ कई महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए। न्यायालय ने आदेश दिया कि आरोपी की मृत्यु के बाद ही उसका शव उसके परिजनों को सौंपा जाएगा। इसके अलावा पीड़िता के पुनर्वास, शिक्षा और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसे 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया।

कानूनी जानकारों का मानना है कि यह फैसला पीड़ितों के अधिकारों और उनकी गरिमा की रक्षा की दिशा में एक मजबूत संदेश देता है।

यह दर्दनाक घटना 15 दिसंबर 2025 की रात गांधीनगर के सेक्टर-24 स्थित इंदिरानगर छपरा क्षेत्र में हुई थी। जांच के अनुसार चार वर्षीय बच्ची अपने घर में सो रही थी, तभी आरोपी उसे उठाकर घर से बाहर ले गया। आरोप है कि उसने बच्ची को पास की झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अपराध को अंजाम देने के बाद वह मासूम को मृत समझकर वहीं छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता है कि कुछ देर बाद वह दोबारा घटनास्थल पर लौटा ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि बच्ची जीवित है या नहीं।

घटना के सबसे मार्मिक पहलुओं में से एक यह रहा कि गंभीर मानसिक और शारीरिक आघात झेलने के बावजूद बच्ची ने असाधारण साहस का परिचय दिया। होश में आने के बाद वह कांपते कदमों से

किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। परिवार द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं और पूरे मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लिया गया।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी की नजर बच्ची पर पहले ही पड़ चुकी थी। वह उसे स्थानीय किराना दुकान के आसपास देख चुका था और कथित तौर पर कई दिनों से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपराध को अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। जांच में यह भी सामने आया कि उसने करीब दस दिन पहले ही इस अपराध की योजना बना ली थी और अवसर की तलाश कर रहा था।

घटना के बाद आरोपी राज्य छोड़कर अपने गृह राज्य बिहार भागने की तैयारी में था। हालांकि पुलिस ने तेजी दिखाते हुए तकनीकी निगरानी, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और मुखबिर तंत्र की सहायता से उसे केवल पांच दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी लगातार अपनी पहचान और लोकेशन छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जांच टीमों की सक्रियता के कारण वह कानून के शिकंजे से बच नहीं सका।

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर पुनर्निर्माण प्रक्रिया के लिए लेकर गई, तब उसने कथित तौर पर पुलिस पर हमला करते हुए भागने का प्रयास किया। अधिकारियों के अनुसार स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि आत्मरक्षा के लिए पुलिस को तीन राउंड फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान एक गोली आरोपी के पैर में लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया। बाद में उसे अस्पताल में उपचार दिलाकर न्यायालय से रिमांड पर लिया गया और आगे की पूछताछ की गई।

मामले की जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। गांधीनगर के पुलिस अधीक्षक रवि तेजा वासम शेट्टी ने बताया कि पुलिस, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) और अन्य जांच एजेंसियों ने मिलकर बेहद मजबूत वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए। घटनास्थल से प्राप्त नमूनों, तकनीकी डेटा, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य फोरेंसिक प्रमाणों ने अभियोजन पक्ष को अदालत में मजबूत आधार प्रदान किया। इन्हीं साक्ष्यों के बल पर आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे सिद्ध किया जा सका।

इस मामले की एक और विशेषता जांच की गति रही। पुलिस ने दिन-रात काम करते हुए केवल 13 दिनों के भीतर आरोपपत्र तैयार कर अदालत में दाखिल कर दिया। सामान्यतः ऐसे मामलों में जांच और दस्तावेजी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है, लेकिन अधिकारियों ने इसे संवेदनशील मामला मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया। अभियोजन पक्ष ने भी गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे मुकदमे की सुनवाई तेजी से आगे बढ़ सकी।

न्यायिक और पुलिस अधिकारियों का मानना है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों में त्वरित जांच और शीघ्र सुनवाई अत्यंत आवश्यक है। लंबी कानूनी प्रक्रिया न केवल पीड़ित परिवार पर मानसिक बोझ बढ़ाती है, बल्कि समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को भी प्रभावित करती है। गांधीनगर के इस मामले में जांच एजेंसियों और न्यायपालिका के बीच प्रभावी समन्वय ने यह साबित किया कि इच्छाशक्ति और संसाधनों के सही उपयोग से गंभीर अपराधों में भी तेजी से न्याय संभव है।

सामाजिक विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सजा के साथ-साथ पीड़ित के पुनर्वास पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। अदालत द्वारा 10 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे बच्ची की शिक्षा, चिकित्सा और भविष्य की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह संदेश भी जाता है कि न्याय केवल अपराधी को दंडित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित के जीवन को पुनः सामान्य बनाने की जिम्मेदारी भी समाज और व्यवस्था की है।

गांधीनगर की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन अब अदालत के फैसले ने यह विश्वास मजबूत किया है कि कानून की पहुंच से कोई अपराधी बच नहीं सकता। मासूम बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए यह फैसला एक कठोर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस की तेज कार्रवाई, वैज्ञानिक जांच, त्वरित आरोपपत्र और फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई ने मिलकर न्याय की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। यह मामला केवल एक अपराधी को सजा मिलने की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था की भी कहानी है जिसने एक मासूम बच्ची की पीड़ा को गंभीरता से सुना और अपेक्षाकृत कम समय में उसे न्याय दिलाने का प्रयास किया। यही कारण है कि इस फैसले को त्वरित न्याय और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की एक प्रेरक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।